वर्ष, 2020 अंक: 3

हर घर जल
जल जीवन मिशन

मिलकर करें काम
बनाएं जीवन आसान

जल जीवन संवाद

दिसंबर, 2020

मिशन निदेशक की कलम से.....

नई दिल्ली
दिसंबर, 2020

आज वर्ष 2020 का आखिरी दिन है। यह समय, बीते वर्ष का मूल्यांकन करने और भावी योजना बनाने का है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोविड-19 महामारी का हमारे जीवन पर सबसे बड़ा विघटनकारी प्रभाव पड़ा है। तथापि, इस देश के लोगों ने सामूहिक रूप से यह दर्शाया है कि हमारे कार्यप्रणाली और संस्थानों के साथ काम करते हुए, हम इस चुनौती का सामना करने और इस पर जीत हासिल करने में सक्षम हैं। विश्व में चारों ओर विभिन्न टीकों की उपलब्धता के साथ ही इसी आशा के साथ नए साल का इंतजार कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा के बाद से और सुशासन दिवस-2019 पर कार्यान्वयन के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश जारी करने के बाद, हर घर में नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए मिशन में कारगर योजना के साथ कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह संतोष की बात है कि अब तक, 3 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। इसके परिणामस्वरूप, अब 6.23 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में उनके घरों तक पीने योग्य शुद्ध जल मुहैया कराई जा रही है।

इस वर्ष के दौरान, प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश ने **'बॉटम अप एप्रोच'** का पालन करते हुए एक व्यापक योजना बनाई है और हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए अपनी लक्षित तिथि तय तय कर ली है। गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने हर ग्रामीण घर तक नल का पानी पहुंचाने का संकल्प पूरा किया है । पूरे देश में, 26 जिलों के सभी घरों और 65 हजार से अधिक गांवों में, कार्यशील नल कनेक्शन उपलब्ध हैं। इससे यह पता चलता है कि इस मिशन का मुख्य सिद्धांत है कि गाँव में कोई भी व्यक्ति इस मूलभूत सुविधा से वंचित न रहे साथ ही इस कार्यक्रम को सख्ती से कार्यान्वित किया जाए।

हम भारतीय हमेशा बच्चों के भविष्य पर निवेश करते हैं। 'धर्म' के बजाय रोग मुक्त जीवन और समग्र विकास सुनिश्चित करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है, । इस भावना के साथ, 2 अक्तूबर, 2020 को प्रत्येक स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) और आश्रमशालाओं, यानी कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आवासीय स्कूलों में पाइपगत पानी का प्रावधान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान पूरे समाज को प्रेरित करता है और इस कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता है। इस अभियान के तहत, यह परिकल्पना की गई है कि पीने योग्य शुद्ध जल न केवल मिड-डे मील में पीने और खाना पकाने के लिए उपलब्ध होगा, बल्कि बच्चों को कोविड-19 से बचाने और शौचालयों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से हैंडवाशिंग के लिए भी उपलब्ध होगा। यह बहुत बड़ी संतुष्टि की बात है कि 3 महीने में, अब तक 4.37 लाख से अधिक ग्रामीण स्कूलों और लगभग 3.70 लाख एडब्ल्यूसी को पीने योग्य शुद्ध जल मिलना शुरू हो गया है। पंजाब और तमिलनाडु के हर स्कूल में नल जल आपूर्ति उपलब्ध है। इसके अलावा, तमिलनाडु के प्रत्येक एडब्ल्यूसी को शुद्ध पेयजल की सुविधा प्रदान की जाती है। दूसरे राज्य भी तेजी से अग्रसर हैं।

यह हमारे सामूहिक संकल्प की गति और पैमाने को दर्शाता है कि हर घर और विशेषकर, बच्चों के घरों-स्कूलों और एडब्ल्यूसी को पीने योग्य शुद्ध जल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोविड-19 महामारी ने हमारी गति को धीमा कर दिया लेकिन हमारे दृढ़ संकल्प को नहीं। अलग-अलग राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में हमारे कुछ सहयोगियों ने पारिवारिक स्तर पर, वायरस का अनुभव किया। तथापि, हम ने इस नेक काम के लिए खुद को फिर से समर्पित कर जीत हासिल की।

सुनिश्चित करें कि हर घर में पानी की आपूर्ति उपलब्ध हो। हमें मौजूदा और नई जल आपूर्ति प्रणालियों के सुधार पर विवेकपूर्ण निवेश करना होगा। प्रत्येक राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों ने 'कम लाभप्रदता परिणामों' पर ध्यान केंद्रित किया है यानी कि मौजूदा पाइपगत जलापूर्ति प्रणाली वाले गाँवों के शेष घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। हमें मार्च, 2021 तक, इस कार्य को पूरा करना है। गुणवत्ता, मात्रा और नियमितता के संदर्भ में पाइपगत जलापूर्ति को मापने और उसकी निगरानी करने के लिए यह मिशन सेंसर आधारित आईओटी उपकरणों को विकसित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भागीदारी में एक बड़ी चुनौती का संचालन किया है जिसे वास्तविक समय के आधार पर गांवों में पानी की आपूर्ति की निगरानी के लिए उपयोग किया जाएगा। कई राज्यों में, प्रायोगिक परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। यह सार्वजनिक उपयोगिता विकसित करने और उसे प्रबंधित करने का पहला कदम है।

दूषित जल के सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर विशेष रूप से बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पहले दूषित जल की जांच करना और फिर उसका समाधान करना महत्वपूर्ण है। इस पृष्ठभूमि में, जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन और एनएबीएल से इसकी मान्यता ली गई है। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 2,300 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं और इन प्रयोगशालाओं को आम जनता के लिए खोल दिया गया है ताकि वे अपने पानी के नमूने को मामूली लागत पर परीक्षण करवा सकें। इसके अलावा, स्थानीय ग्रामीण समुदाय पानी की आपूर्ति और/ या स्रोत की गुणवत्ता पर निगरानी रखने में सक्षम है, फील्ड परीक्षण किट (एफटीके) द्वारा नियमित रूप से पानी का नमूना परीक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। डी.पी.आई.आई.टी. की भागीदारी में संचालित 'वहनीय घरेलू जल गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों' को विकसित करना एक बड़ी चुनौती है, जिससे इस क्षेत्र में क्रांति आने की संभावना है। समयबद्ध तरीके से जेजेएम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एक व्यापक योजना की आवश्यकता है। पांच वर्षों के लिए ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.), 15वें वित्त आयोग के साथ-साथ चलने वाली योजना तैयार की जाती हैं ताकि पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराये जा रहे फंड से घरों में सुनिश्चित जलापूर्ति के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य किया जा सके। इन ग्राम योजना को जिला कार्य योजना (डी.ए.पी.) तैयार करने के लिए जिला स्तर पर संकलित किया जाता है, जिन्हें राज्य स्तर पर संकलित करके राज्य कार्य योजना (एस.ए.पी.) बनायी जाती है। राज्य कार्य योजना को क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं, बल्क जल आपूर्ति और वितरण परियोजनाओं आदि जैसी परियोजनाओं को कवर करना होगा ताकि राज्य में पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इस मिशन में हर गाँव/ बस्ती में चिनाई, प्लंबिंग, फिटिंग, बिजली, पम्प मैकेनिक्स आदि क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिनकी सेवाओं का उपयोग जल आपूर्ति योजनाओं के निर्माण के साथ-साथ नियमित सञ्चालन और रखरखाव के निर्माण में किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधनों का ऐसा पूल जहां गाँवों को नियमित रूप से आत्मनिर्भर इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणालियों के रख-रखाव के आत्म निर्भर भारत के विचार के अनुरूप होगा। इस कार्यक्रम को रोजगार के अवसर प्रदान करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता कर रहा है, जिसमें गांवों का दौरा करने वाली टीमें शमिल होंगी ताकि विवेकपूर्ण निवेश पर ध्यान देते हुए कार्यान्वयन की समीक्षा तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर कार्यान्वयन में तेजी लाए जा सके। सामुदायिक भागीदारी और त्वरित कार्यान्वयन हेतु किए गए संस्थागत व्यवस्थाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ये टीमें जीपी/ वीडब्ल्यूएससी सदस्यों और स्थानीय समुदाय के साथ-साथ पीएचईडी के अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखेंगे । यह उल्लेखनीय है कि स्थानीय ग्रामीण समुदाय, गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह, क्षेत्रक भागीदारों द्वारा जल जीवन मिशन को सही मायने में लोगों का कार्यक्रम बनाने में एकजुट हुए हैं। हम उन सभी को सलाम करते हैं, जिन्होंने इस नेक मिशन के लिए खुद को समर्पित किया है। इस अंक में, आपको उस क्षेत्र से कई कहानियाँ मिलेंगी जहाँ प्रेरणादायक कार्य किए गए हैं।

वर्ष 2020 के दौरान, कोविड-19 महामारी के बावजूद, हम सभी लोगों को अनुकरणीय कार्य करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम सिद्ध हुए हैं। कल ही अलग-अलग राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ प्रगति में जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान, प्रधानमंत्री ने कार्यान्वयन को फिर से आगे बढ़ाने और नियोजित तारीख से पहले इसे पूरा करने की अपील की। मुझे यकीन है कि प्रत्येक राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए जनादेश पर काम करना शुरू कर दिया है। मौजूदा वित्त वर्ष की केवल अंतिम तिमाही शेष है। पिछली तिमाही के साथ-साथ अगले वित्तीय वर्ष की प्रगति और योजना की समीक्षा करें। इन प्रयासों के साथ, आने वाले महीनों में परिणाम दिखाई देंगे।

नए वर्ष 2021 की पूर्व संध्या पर, मैं यहां अपने सहयोगियों के साथ, आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको बधाई देता हूं और आपको और आपके सहयोगियों के साथ-साथ संबंधित परिवारों को भी नए साल की शुभकामनाएं देता हूं।

(भरत लाल)
अपर सचिव एवं मिशन निदेशक
जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन

राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की। इस मिशन को एकमात्र उपायों के साथ यानी स्रोत से आपूर्ति तक से लेकर पुनर्उपयोग और पुनर्भरण तक एकीकृत दृष्टिकोण के साथ डिजाइन किया गया है। 'हर घर जल' कार्यक्रम को 'जन आन्दोलन' -लोगों का आंदोलन के रूप में परिकल्पित किया गया है।

जल जीवन मिशन वर्ष 2024 तक गांवों में कार्यशील ग्रामीण नल कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की भागीदारी में कार्यान्वित किया जाता है। जल जीवन मिशन एक कार्यक्रम है जहां ग्रामीण भारत की महिलाओं और युवतियों द्वारा सामना किए जाने वाले कड़े श्रम से मुक्ति मिली है उन्हें अपने दैनिक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पीने योग्य जल लाने के लिए हर रोज दूर पैदल चलना पड़ता है।

विज़न

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को **नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा** में पेयजल आपूर्ति मुहैया करना जिससे ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

प्रधानमंत्री द्वारा 34वीं प्रगति वार्ता के तहत जेजेएम की समीक्षा

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर, 2020 को सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए 34वीं प्रगति (सक्रिय शासन और समय पर क्रियान्वयन) की अध्यक्षता की।

इस बातचीत के दौरान, उन्होंने समय-सीमा के भीतर लक्ष्य को पूरा करने के लिए जेजेएम को मिशन मोड में कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित किया। अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों की सराहना करते हुए, प्रधान मंत्री ने अन्य राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 'हर घर जल' सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने को कहा क्योंकि इस मिशन से जल-जनित रोगों, कुपोषण आदि की समस्याओं का समाधान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार लाएगा।

देश में प्रगतिशील एफएचटीसी कवरेज (31 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)

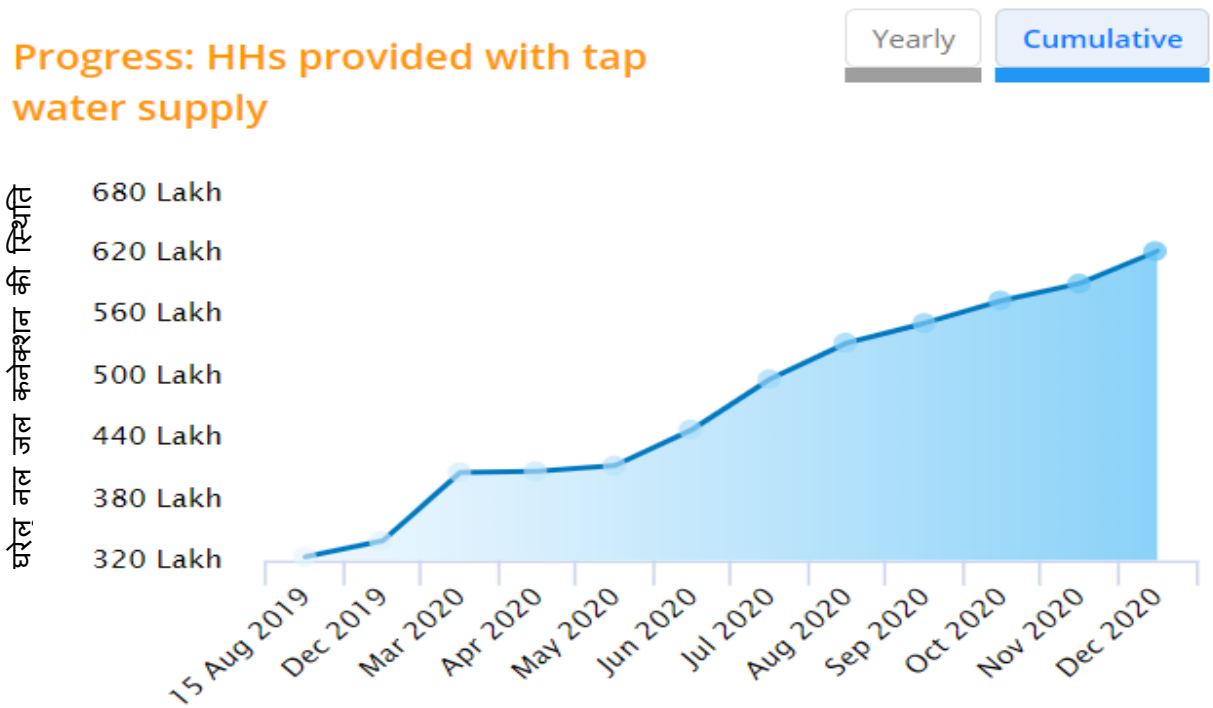

31 दिसंबर, 2020 तक तुलनात्मक FHTC कवरेज की स्थिति

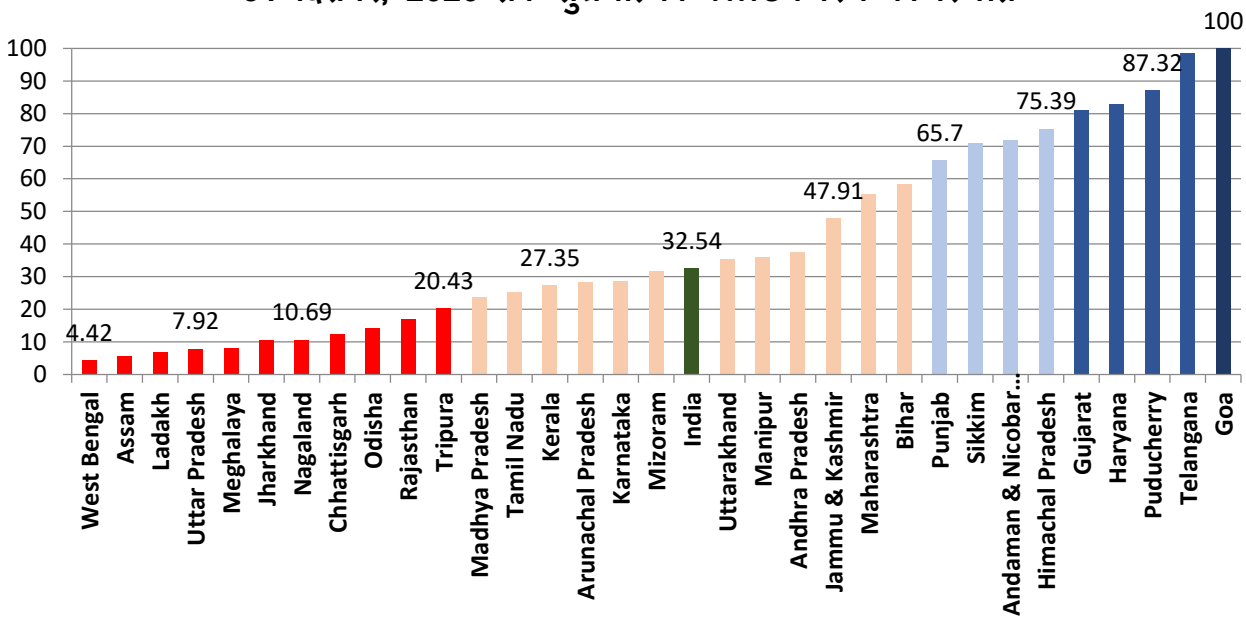

वर्तमान में, भारत में 32.54 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध है जबकि 15 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में नल कनेक्शन के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत से अधिक है, 17 राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश क्षेत्र राष्ट्रीय औसत से कम है। गोवा 'हर घर जल राज्य' बनने वाला पहला राज्य बन गया है। तेलंगाना राज्य भी 100% हर घर जल को प्राप्त करने के करीब पहुंच रहा है। पुदुचेरी, हरियाणा और गुजरात ने अपने 80% से अधिक ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान किए हैं।

मिशन की शुरुआत के बाद से उपलब्ध कराए गए FHTCs (15 अगस्त, 2019)

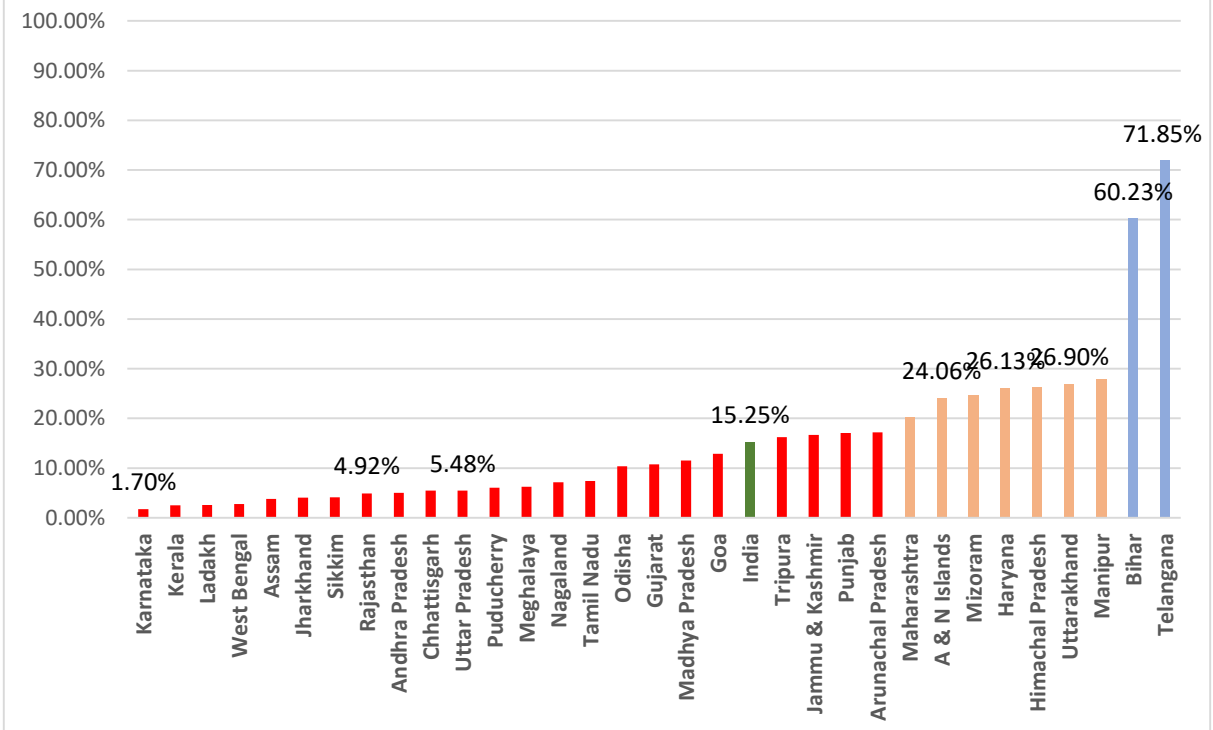

हर घर जल
जल जीवन मिशन

India | Status of tap water supply in rural homes

Total number of households (HHs)	Households with tap water connections as on 15 Aug 2019	Households with tap water connections as on date
		+1,73,638
19,13,80,214	3,23,62,838	6,22,83,779
	(16.91%)	(32.54%)

Har Ghar Jal [100 % HHs with tap water connections]

100 % FHTC States/ UTs

Goa

100 % FHTC Districts	100 % FHTC Blocks	100 % FHTC Panchayats	100 % FHTC Villages
26	454	34,787	65,388

15 अगस्त, 2019 की स्थिति के अनुसार

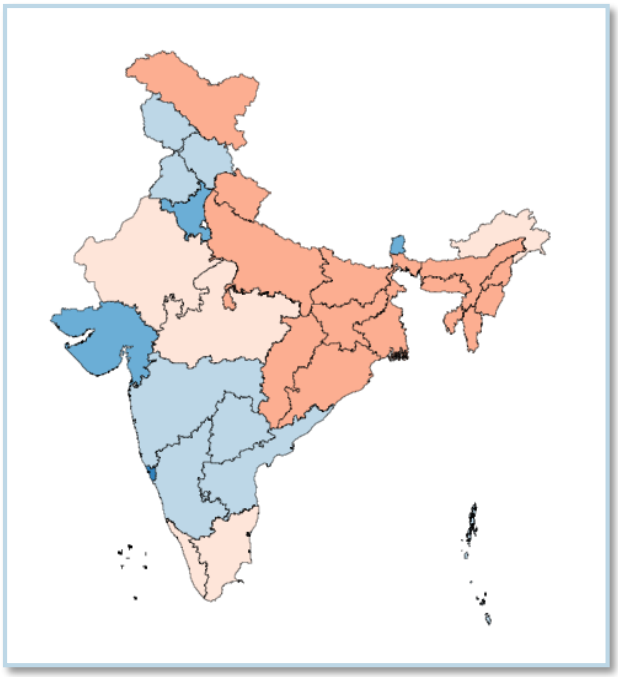

31 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार

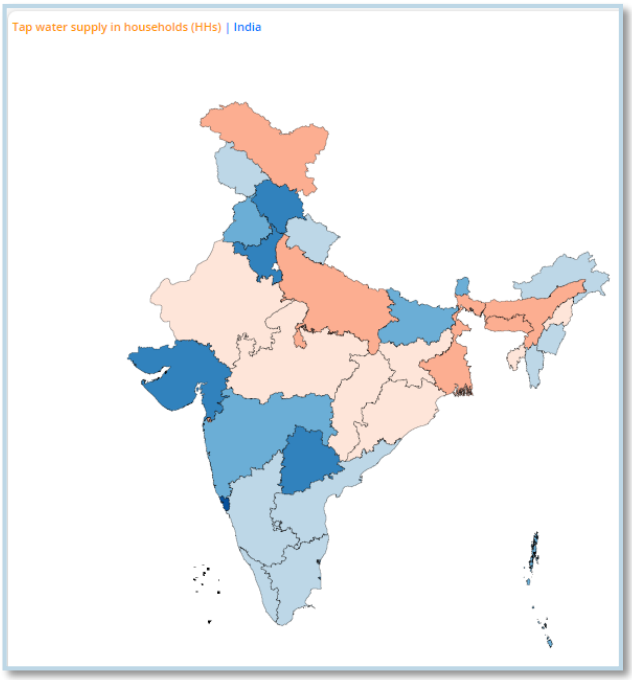

0%-10% 11%-25% 26%-50% 51%-75% 76%-<100% 100%

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

जम्मू व कश्मीर में जल आपूर्ति सेवा प्रदायगी का विकेन्द्रीकरण

"जम्मू के राजौरी जिले के सुंदरबनी की ऊपरी कांगड़ी की महिला सरपंच रुक्मेश कुमारी अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, " मैंने घुसपैठ और गोलाबारी की आवाज़ के साथ जीना सीख लिया है। उनका कड़ा और रचा-बसाया एक सभ्य जीवन की तलाश में उनके गाँव द्वारा सामना किए जा रहे संघर्षों का प्रमाण है। सीमा के आसपास के गांवों को बुनियादी ढांचे और सेवाओं से संबंधित समस्याओं की अति रक्त-प्रवाह से त्रस्त किया गया है। इस क्षेत्र में जल आपूर्ति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।"

दूर-दराज बस्तियों वाले ग्राम कांगड़ी, 1,500 घरों के साथ पहाड़ी पुल के रास्ते के जरिए खराब सड़कों से जुड़ा हुआ है। घने जंगल से आच्छांदित और बिखरी हुई आबादी वाला यह गांव नोशेरा सेक्टर में एलओसी से केवल 5 किमी दूर है। वर्षों से, स्थानीय निवासी अपनी दैनिक जल की जरूरतों के लिए दूर स्थानों पर अवस्थित स्थानीय झरनों और तालाब पर निर्भर थे। ग्रामवासियों ने दूर के इलाकों से पानी लाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया।

चूंकि, गर्मियों में स्थानीय झरनों और तालाबों में पानी का प्रवाह कम हो जाता है, अत: ग्रामवासी पानी की तलाश में संघर्ष करते रहते हैं।

जबकि बरसात के मौसम में इन स्रोतों पर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन जलधारा नदियों और नालों से सतह के पानी से प्रदूषित हो जाती है, जिससे जल-जनित रोग बढ़ जाते हैं। मार्च, 2020 में अंभखोरी में शुरू की गई जलापूर्ति योजना को इस तरह की बुनियादी सेवा की कमी के कारण किए जाने वाले कड़े श्रम को समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। सभी घरों में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत रेट्रोफिटिंग का काम शुरू किया गया। जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है, जबकि जम्मू और कश्मीर ने राष्ट्रीय लक्ष्य से वर्ष 2022 तक इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध किया है।

सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कार्यशील नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है। जम्मू व कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 के हालिया संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों को लोगों-जिला विकास परिषद, हलका पंचायत और ब्लॉक विकास परिषद द्वारा सीधे निर्वाचित एक त्रिस्तरीय संरचना के साथ मजबूती प्रदान की गई है। ये निकाय जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में सहायता करेंगे। पानी समितियों के क्षमता निर्माण के लिए कार्यान्वयन सहायता एजेंसियां नियोजित की जा रही हैं ताकि समुदायों को केंद्र शासित प्रदेश के यूटी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग से तकनीकी सहायता के साथ-साथ उनके जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, कार्यान्वयन, प्रचालन व रखरखाव करने का अधिकार हो।

आंगनवाड़ी केन्द्रों, आश्रमशालाओं और स्कूलों में पाइपगत जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए 100 दिवसीय अभियान

माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2020 को 'कार्य करने का आह्वान' किया, जिसमें राज्य सरकारों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से आग्रह किया गया कि वे देश के प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र, आश्रमशाला और स्कूलों में सुनिश्चित नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करें जिसकी शुरूआत 2 अक्टूबर, 2020 को की गई थी।

100 दिवसीय अभियान का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्कूल के शिक्षकों, स्कूल प्रबंधन समिति के बीच वॉश के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना; बच्चों को कौशल संबंधी शिक्षा देकर

उनको पूर्ण एकीकृत जीवन प्रदान करने में सहायता देना; प्रमुख व्यक्तिगत साफ-सफाई पर ध्यान केंद्रित करना - समग्र जल सुरक्षा और संरक्षा, सुरक्षित प्रचालन और भंडारण, साबुन से हाथ धोना और व्यक्तिगत और सामुदायिक साफ-सफाई; और अंत में सभी हितधारकों के साथ प्रभावी साझेदारी करके जल को 'सभी का सरोकार' बनाना है।

इस अभियान के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित करने हेतु राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों और जिले के अधिकारियों की सहायता के लिए अभियान के दिशानिर्देश 2 अक्टूबर, 2020 को जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों के साथ-साथ, एक स्वतंत्र रिपोर्टिंग ढांचा बनाया गया है जो न केवल वास्तविक और वित्तीय प्रगति के आकलन में सहायता करता है बल्कि इस प्रक्रिया में और तेजी लाने के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना भी पैदा करती है। राज्य अलग-अलग बहु-आयामी कार्यनीति अपना रहे हैं। मौजूदा पाइप जेल आपूर्ति को रेट्रोफिट और/ या संवर्धित किया जा रहा है जहां संस्थानों को निष्क्रिय या खराब नल कनेक्शन प्रदान नहीं किए जाते हैं।

गाँवों में उन संस्थानों के लिए आवश्यक जल शोधन प्रणाली के साथ स्वचालित जलापूर्ति योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिनका इस वर्ष कोई पीडब्ल्यूएस प्रस्तावित नहीं है। पहाड़ी/ वनांच्छादित/ रेगिस्तानी/ आदिवासी क्षेत्रों जैसे विरल बसावटों जहां कोई पीडब्ल्यूएस मौजूद नहीं है वहां के संस्थानों में सौर ऊर्जा स्वचालित जल आपूर्ति प्रणालियों को विकसित किया जा रहा है। संस्थानों में 'जलमणि' के तहत उनकी कार्यक्षमता का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है और उन स्थानों के लिए प्राथमिकता दी जा रही है जहां मरम्मत/पुनः बहाली संभव है; जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र संस्थापित किए जा रहे हैं।

कार्यशील नल कनेक्शन प्रदान करने के अलावा, ग्रे-वाटर और वर्षा जल संचयन के स्व-स्थाने उपचार पर जोर दिया गया है। समग्र जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल-संकटग्रस्त, सूखाग्रस्त, पहाड़ी, वनांच्छादित क्षेत्र और रेगिस्तानी इलाकों में प्रावधान किए जा रहे हैं। इस अभियान में पौधे की नर्सरी, पौधों को पानी देना, पीने योग्य शुद्ध जल के बारे में ज्ञान साझा करना और बड़ी पर्यावरणीय शिक्षा के हिस्से के रूप में इसकी गुणवत्ता का पता लगाने के लिए मापदंडों को शामिल करती हैं।

अच्छे स्वास्थ्य के लिए वाश की प्रमुखता को देखते हुए, इसके महत्व को मौजूदा कोविड-19 महामारी की स्थिति में और महसूस किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं तथा स्कूलों और समुदायों में अच्छे वाश व्यवहार और आदतों को सुनिश्चित करने से मानव-से-मानव संचरण को रोकने में मदद मिलेगी और इससे सार्स-कोव-2 वायरस के फैलाव को रोका जा सकेगा, जिससे कोविड-19 पैदा होता है। इनमें से कई संस्थानों ने कोविड-19 देखभाल केंद्र के रूप में काम किया है, और इस तरह स्वच्छता सुनिश्चित करना तथा बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार करना प्राथमिकता है। इसलिए, जब स्कूल कोविड-19 महामारी के बाद फिर से खुलते हैं और इन संस्थानों में गतिविधियाँ शुरू होती हैं, तो पीने, मध्याह्न भोजन पकाने, हाथ धोने और शौचालय के लिए सुरक्षित पानी उपलब्ध होनी चाहिए । यह हमारे युवाओं के लिए एक आदर्श उपहार होगा।

सामुदायिक स्वामित्व: जल जीवन मिशन के साहसिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ओडिशा के अनुभव

-लिबी जॉनसन
ईडी, ग्राम विकास ट्रस्ट

जल जीवन मिशन ने एक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के साथ भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कवर करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लोगों के आंदोलन के रूप में इसे प्राप्त करने की परिकल्पना करता है, जहाँ लोगों और उनके प्रतिनिधि संस्थानों द्वारा पेयजल आपूर्ति का स्वामित्व और प्रबंधन किया जाता है। एक बार लक्ष्य हासिल करने के बाद, यह वित्त-पोषण और कार्यों के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को प्राप्त करने और अपने नागरिकों की मांगों का प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्थानीय शासन संस्थानों को मजबूत करने के सबसे साहसिक तरीकों के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

ओडिशा में एक गैर-सरकारी संगठन, ग्राम विकास, 1995 से गांवों में सामुदायिक स्वामित्व और प्रबंधित एकीकृत जल और स्वच्छता मध्यवर्तन (इंटरवेंशन) को बढ़ावा दे रहा है। ओडिशा सरकार और दाता (Donor) एजेंसियों की भागीदारी में इन मध्यवर्तनों से 82,000 घरों को कवर करने वाले 1,400 से अधिक ग्राम समुदायों को लाभ हुआ है।

'ग्राम विकास का अनुभव बताता है कि अधिकांश दूरस्थ क्षेत्रों में भी ग्राम समुदायों द्वारा स्वामित्व और प्रबंधित एकल ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों का निर्माण करना संभव है। इसके लिए आवश्यक संस्थागत और तकनीकी क्षमताओं का निर्माण किया जा सकता है और समुदायों ने पूंजीगत लागत के एक हिस्से के साथ-साथ प्रचालन और रखरखाव की लागत का एक बड़ा हिस्सा भुगतान करने के लिए प्रेरित किया। 626 गांवों में लगभग 41,500 घरों को कवर करने वाले एक हालिया सर्वेक्षण में, जहां ग्राम विकास ने नल जलापूर्ति प्रणालियों के निर्माण का समर्थन किया था, यह दर्शाता है कि सर्वेक्षण में शामिल 87% परिवारों ने अपने घरों में एक कार्यशील नल कनेक्शन की सूचना दी थी। इन गांवों में यह मध्यवर्तन 1995 और 2018 के बीच के वर्षों के दौरान हुआ था। यह उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षण में शामिल केवल 67% परिवार ही इस मध्यवर्तन का हिस्सा रहे जब इस कार्यक्रम को उनके गांवों में चलाया गया था। ग्राम विकास ने इन गाँवों को अलग करने के बाद ही केवल 33% परिवार इस कार्यक्रम में शामिल हो पाए, और संबंधित सामुदायिक संस्थानों द्वारा पाइप जलापूर्ति व्यवस्था का प्रबंधन किया गया।

ग्रामीण भारत में सामुदायिक प्रबंधित नल जलापूर्ति प्रणाली की सफलता को सक्षम बनाने वाले कारक क्या हैं?

ग्राम विकास का अनुभव यह सुझाता है कि इसके लिए निम्नलिखित चार सिद्धांत आवश्यक हैं और इसके लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं:

1.) यह आवश्यक है कि एक गांव में 100% घरों को सभी चरणों में शामिल किया जाए। कोई भी घर, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उन्हें इस मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं रखा जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि गरीब लोगों और सामाजिक रूप से बहिष्कृत लोगों को इस मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं रखा जाए। यदि शुरुआत से शामिल नहीं किया गया, तो इसमें बहुत संभावना है कि गरीब लोगों को बाद में शामिल होना मुश्किल होगा, खासकर उन गांवों में जहां गांव बंटे हुए हैं। सेवा साम्यता की भावना के अलावा, सभी या कोई भी दृष्टिकोण पूरे गाँव के लिए एक साझा उद्देश्य के लिए एक साथ काम करने का एक अनूठा अवसर पैदा करता है।

2.) हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना और सकारात्मक कदम उठाते हुए यह सुनिश्चि करना कि महिलाओं और गरीब तबकों को प्रबंधन में शामिल किया जाए। हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के अलावा, भले ही एक सीमित तरीके से, इस तरह की समावेशी प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि इस सुविधा को व्यवस्थित तरीके से और सभी के लाभ के लिए जारी रखा जाए।

3.) सभी को लागत साझा करनी होगी। प्रारंभिक पूंजी लागत में एक महत्वपूर्ण योगदान पर जोर देना और यह कि लोगों को लागत वहन करने और इस सुविधा को बरकरार रखना लोगों के दांव को बनाने में मदद मिलती रहे।

4.) इसमें यह बल दिया गया हैं कि लोगों में आम सहमति पैदा करने के लिए पहले चरण से ही उत्तरदायित्व संभालना, स्थानीय अंशदान जुटाना, निर्माण कार्य का प्रबंधन करना और प्रचालन व रख-रखाव का भार संभालना स्थायित्व सुनिश्चित करने का एक स्वस्थ तरीका हो। यह एक दूसरे के साथ और बाहरी लोगों के साथ संवाद करने और एक साथ काम करने का समुदाय में एक अनुभव पैदा करता है।

उनके द्वारा लिए गए ये चार सिद्धांत सफल नहीं होंगे। इसमें समावेशी, भागीदारी, लागत-साझाकरण और जिम्मेदारी लेना शामिल है – ये शुरुआत से ही एक स्थायी और प्रभावी प्रक्रिया बनाने में मदद करेगा। इन मूलभूत सिद्धांतों को तीन प्रमुख मध्यवर्तन के साथ पूरा करने की आवश्यकता है। सामुदायिक संस्थानों का निर्माण प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता आवश्यक है।

प्रशासनिक और प्रबंधन पहलुओं और प्रभावी नेतृत्व के लिए प्रेरक तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा करने की आवश्यकता है।

क्षमता कौशल का निर्माण करने के लिए एक्सपोज़र विज़िट एक अच्छा तरीका है। गांवों के पुरुषों और महिलाओं को प्लंबिंग, पाइपलाइन की मरम्मत और पंपिंग सिस्टम के रखरखाव के लिए तकनीकी पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में अधिकतर कार्य 'कार्य के दौरान (ऑन-द-जॉब)' हो सकता है जबकि प्रारंभिक कार्य गाँव में ही किया जाता है। आवधिक पुनश्चर्चा और व्यावहारिक प्रशिक्षण आगे क्षमता का निर्माण करने में मदद कर सकते हैं।

इस ग्राम विकास से प्रत्येक गांव को प्रत्येक घर से योगदान के साथ एक कोष निधि स्थापित करने में मदद मिली है। ग्राम संस्थान द्वारा बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में फंड का निवेश किया जाता है और उसका प्रबंधन किया जाता है जोकि एक 'स्थायी संसाधन' के रूप में जरूरतें पूरी करती है। 'कॉर्पस फंड से मिलने वाले ब्याज का इस्तेमाल नए घरों में सेवाओं के विस्तार और प्रमुख रखरखाव जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

अनुरक्षण निधि एक आवर्ती वित्तीय साधन है जो बिजली के शुल्क, तकनीकी कर्मियों के वेतन तथा नियमित मरम्मत व रखरखाव जैसे पाइप जल आपूर्ति प्रणाली के प्रचालन और रखरखाव की लागतों को पूरा करने में मदद करता है। रखरखाव संबंधी निधि जुटाने के लिए गांवों ने कई तरीके विकसित किए हैं। सभी संबंधित ग्राम समितियां मासिक शुल्क का भुगतान करने के लिए सभी परिवारों को शुल्क निर्धारित करती हैं। कुछ गांवों में, फसल के समय सकल उत्पाद का अनुपात (0.25% -0.50%) रखरखाव निधि में योगदान किया जाता है। कई गाँवों में, मत्स्यपालन वाले गाँव के तालाब अथवा लकड़ी के लॉट या बागों के रूप में विकसित आम बंजर भूमि जैसे सामान्य संपत्ति संसाधनों से प्राप्त आय को रखरखाव निधि में जमा किया जाता है, इस प्रकार खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

जल की जांच हेतु 'पोर्टेबल उपकरणों' के विकास के लिए नवाचार चुनौती की शुरूआत

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति भूजल (80%) और सतही जल (20%) स्रोतों से होती है। तथापि, घटते भूजल स्तर के कारण, विशेष रूप से शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में, सतही जल का उपयोग बढ़ रहा है। भूजल और सतही जल आधारित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणाली दोनों के लिए, पीने योग्य शुद्ध जल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक क्षेत्र-विशिष्ट संदूषण को मापना महत्वपूर्ण है। समरूप पेयजल गुणवत्ता प्रोटोकॉल, 2019 ने बीआईएस आईएस 10500: 2012 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार पीने के जल की वहनीयता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों को निर्दिष्ट किया है।

नल द्वारा पानी की आपूर्ति प्राप्त करने वाले लोगों के पास अपने घरों तक अपने नलों से आने वाले पानी की क्षमता का जांच करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इससें ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां लोग सीधे नल के पानी का सेवन करने से हिचकते हैं। शहरी क्षेत्रों में लोग अतिरिक्त खर्च के कारण घरेलू जल उपचार इकाई स्थापित करते हैं।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जल परीक्षण के लिए सुवाह्य उपकरणों को विकसित करने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार की भागीदारी में एक नवाचार चुनौती का प्रारंभ किया है। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य सुवाह्य उपकरणों को विकसित करने के लिए एक अभिनव, मॉड्यूलर और लागत प्रभावी समाधान लाना है, जिसका उपयोग घरेलू स्तर पर पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच आसानी से और सही तरीके से किया जा सकता है।

नवाचार चुनौती का लक्ष्य यह है कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्थानों पर जल स्रोतों की जांच हो, ताकि नीति निर्माताओं को जल संदूषण से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में सहायता मिल सके। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता की जांच को प्राथमिकता दी जाती है।

असम में कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण

सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 'कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन' उपलब्ध कराना है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गांवों में कुशल मानव संसाधन और जलापूर्ति सामग्रियों की तत्काल आवश्यकता है ताकि अपेक्षित निर्माण कार्य हो सके। कार्यक्रम को चलाने के लिए क्षेत्र में मुख्य रूप से मज़दूरों, इलेक्ट्रिशियन, फिट्टर, पंप ऑपरेटर और मेकैनिक की आवश्यकता होती है।

कार्यक्रम को तीव्र गति से चलाने तथा इसे व्यापक स्तर पर बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है। इसके अलावा, कार्यान्वयन चरण के बाद, स्कीमों के दीर्घ कालीन स्थायित्व हेतु ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों (जीपी)/इसकी उप-समितियों अर्थात् वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति द्वारा इनके प्रचालन एवं रख-रखाव (ओएण्डएम) के लिए भी स्थानीय स्तर पर बहुत अधिक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है।

कोविड-19 महामारी के कारण काफी बड़ी मात्रा में मज़दूर अपने गांवों/बस्तियों में लौट गए हैं। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रवासी कार्यबल को कोई लाभकारी रोज़गार दिया जाए और यह भी ध्यान दिया जाए कि इससे उनका कौशल विकास हो।

देश के विभिन्न गांवों में चल रहे विकास कार्यों पर नज़र रखी जा सकती है जिससे यह सुनिश्चित हो कि लोग जलापूर्ति कार्यों में कार्य करके धनार्जन कर सकें।

ग्राम पंचायतों में कुशल मानव बल की मौजूदगी से लम्बे समय तक नलों की कार्यशीलता और जलापूर्ति प्रणालियों का रख-रखाव सुनिश्चित हो सकेगा। सभी ग्राम पंचायतों में विश्वसनीय मानव संसाधन उपलब्ध कराने का उद्देश्य है ताकि लम्बे समय तक नियमित जलापूर्ति उपलब्ध कराई जाती रहे।

इस संदर्भ में, नवम्बर में असम सरकार द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। श्री रिहन डायमरी, मंत्री, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने गुवाहाटी में जल जीवन मिशन के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण का औपचारिक उद्घाटन किया।

असम का लक्ष्य वर्ष 2024 तक 63.35 लाख परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है जिनमें से 13 लाख परिवारों को वर्ष 2020 में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2024 तक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मौजूदा कुल 8,033 जल कनेक्शनों की मरम्मत की जाएगी जबकि 15,000 से 20,000 परियोजनाओं को स्थापित किया जाएगा। राज्य-भर में स्थानीय युवाओं को कौशल संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों को सूचिबद्ध करने के लिए पीएचईडी असम ने असम कौशल विकास मिशन (एएसडीएन) के साथ तालमेल किया। कार्यक्रम के लिए आवश्यक कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल संसाधनों के आधार पर तीन स्तरों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पहले चरण में 2,640 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सफल प्रशिक्षण के उपरांत 2 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा के साथ-साथ उन्हें प्रमाणपत्र दिया जाएगा। 27 नवंबर, 2020 को शुरू किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में 60 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। असम में विभिन्न कार्यों के लिए 50,000 लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना है। असम में यह कौशल प्रशिक्षण जेजेएम तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि आगे बेरोजगारी की समस्या को भी दूर करेगा।

आवाम की आवाज

मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन: नल जल कनेक्शन प्रदान करके घरेलू जल सुरक्षा में सुधार

नर्मदा नदी के दक्षिण भाग में स्थित सतपुरा पहाडों की गोद में बसे बारवानी जिले में गर्मी के मौसम में ऊंची-नीची सूखी चट्टाने भरी होती हैं जो वर्षा ऋतु में फिर हरी-भरी घाटी बन जाति है। जल की उपलब्धता के बावजूद इस जिले को अर्ध-शुष्क क्षेत्र माना जाता है क्योंकि यहां का पानी बह जाता है तथा यहां जल संरक्षण तथा पुनर्भरण के उपायों की कमी है। गर्मियों में जिले की ज्यादातर आबादी को जल संकट का सामना करना पड़ता है। समस्या की गंभीरता के कारण, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की सफलता की कहानी विशिष्ट है क्योंकि सामुदायिक स्वामित्व और जिला प्रशासक के नेतृत्व में तेज़ी से कार्यान्वयन हुआ है। वर्ष 2021 तक, बारवानी में 51,679 ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से देश के प्रत्येक परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि जल का बेहतर उपयोग हो सके। युनीसेफ से तकनीकी सहायता लेकर मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने पेयजल परियोजनाओं की आयोजन, कार्यानवयन और प्रचालन के लिए पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को समर्थन देना शुरू किया।

अब तक, युनीसेफ ने क्षमता संवर्धन किया और राज्य-भर में 5,700 कुशल हितधारकों का निर्माण किया। उन्हें कैसकेड दृष्टिकोण अपनाकर मंडलीय, जिला और ग्राम-स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया। गांव की पाइपड जलापूर्ति ढांचे को सुदृढ़ करने पर बल दिया जा रहा था जिसके लिए यह आवश्यक हो गया है कि पाइपों और घरेलू ढ़ांचों की मरम्मत, जल शोधन, ग्रे-वाटर प्रबंधन और समग्र प्रचालन एवं प्रबंधन कार्य के लिए उपलब्ध तकनीकी मध्यवर्तनों को समझा जाए।

आगामी संभावित चुनौतियों को हल करने के लिए रोडमैप तैयार करने में पीएचईडी की सहायता की गई जिसके लिए प्रारंभ में कमियों को पहचाना गया और क्षमता संवर्धन प्रयासों के लिए कैलेण्डर बनाया

गया, जिसमें कार्य को विभिन्न चरणों में बांटा गया। पारंपरिक तौर पर, लोगों को प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता था। परंतु महामारी के दौरान सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए यह प्रशिक्षण आभासी तौर पर (वर्चुअल रूप से) दिया गया।

चार प्रमुख जिलों – बारवानी, गूना और इंदौर में ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार किया जा रहा है, जिसमें भविष्य के प्रबंधन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समुदाय स्वामित्व को प्रभावी रूप से एकीकृत किया गया है और जिला कार्य योजना (डीएपी) में इसे शामिल किया जाएगा ताकि पेयजल सुरक्षा प्राप्त हो सके। पंचायती राज संस्थान के सदस्यों (सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक), महिला एवं बाल विकास विभाग के सदस्यों (आगंनवाडी अधिक्षक, कार्मिक और सहायिका), शिक्षा विभाग के सदस्यों (राज्य शिक्षा केंद्र अधिकारी और शिक्षक), स्वास्थ्य विभाग के सदस्यों (आशा कार्यकर्ता) और ग्रामीण जल जीवन मिशन (स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं) सभी को एकजुट किया गया है।

आपसी ज्ञान साझा करने के लिए मंच उपलब्ध कराने और सुदृढ़ निगरानी सुनिश्चित करने के लिए डेटाबेस तैयार किया गया है और इसे नियमित रूप से एक व्यापक मोबाइल आधारित ऐपलिकेशन 'एम-वाटर पोर्टल' पर अपलोड किया जाता है ताकि इन्हें वीएपी सूचना में समेकित किया जा सके। विभिन्न फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और समुदायों के नेताओं के समर्थन से राज्य आंगनवाडियों (स्कूल पूर्व केंद्रों), स्कूलों और घरों की संख्या का पता लगा सकेगा जिनमें कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने हैं। पोर्टल के अलावा विभिन्न ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) के बीच सरल संवाद देते और ज्ञान साझा करने के लिए वाटसअप ग्रुप भी बनाए गए हैं। आईईसी सामग्री उपलब्ध कराने, पीआरए को मार्गदर्शन देने और चौपाल (ग्राम बैठक) जैसी ग्रामीण गतिविधियों में मार्गदर्शन देने, पीआरआई सदस्यों को प्रशिक्षण देने तथा निर्माण के निरीक्षण के लिए भी सहायता दी जा रही है।

बारवानी गांव के निवासी विजय मेहरा के लिए यह मिशन पहले ही बहुत बड़ी सफलता बन गया है। उनके गांव में न हैंडपंप था न ही ट्यूबवेल और आंगनवाडियों तथा स्कूलों में खुले कुए के अलावा कोई ओर व्यवस्था नहीं थी। उनकी पत्नी मंजू और दोनों बेटियों को प्रतिदिन परिवार के जल की आवश्यकता के लिए एक चौथाई मिल जाना पड़ता था। विजय दिव्यांग है और वे चाह कर भी मदद नहीं कर पाते थे। परंतु उनके हिम्मत ने उनकी शारीरिक अक्षमता को दरकिनार कर दिया और उन्होने भागीदारी पूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) प्रक्रिया के संबंध में पहल करने पर संवाद करके स्थानीय समुदाय को जागृत किया, इस दौरान उन्होंने गांव के विभिन्न भागों के जल स्रोतों का मूल्यांकन किया और मौसमी मुद्दों पर चर्चा की तथा आधारभूत सर्वेक्षण करवाया जिसे बाद में वीएपी में शामिल किया गया। इस प्रकिया के दौरान मंजू स्वाभाविक नेता के रूप में उभरी और उन्हें वीडब्ल्यूएससी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

वीडब्ल्यूएससी जल और इससे संबंधित स्वास्थ्य और जल गुणवत्ता निगरानी के मुद्दों पर केंद्रित है और इसके लिए क्षेत्र जांच किट के उपयोग का प्रदर्शन करता है, निर्माण गतिविधियों तथा ग्राम स्तर पर सामग्रीयों की निगरानी करता है। जल आपूर्ति परियोजनाओं के प्रचालन एवं रखरखाव के लिए स्थानीय मेकेनिकों, प्लम्बरों और तकनीशियनों को सूचीबद्ध करके स्थानीय निर्माण कार्य को गति मिली है। इस सूचिबद्ध प्रक्रिया से कार्यान्वयन के दौरान प्रगति की निगरानी, व्यय और योजना बनाने में सहायता मिली है।

"आज गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है क्योंकि जल्द ही 339 परिवारों को घरेलू नल जल कनेक्शन मिलने वाला है जिससे समुदाय में सभी के लिए समान रूप से जलापूर्ति हो सकेगी।"

देहरादून के कल्सी ब्लॉक के लेलता गांव में प्रत्येक परिवार को नल जल कनेक्शन मिला

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शहर से लगभग 100 किमी की दूरी पर पहाड़ी घाटियों में बसे लेलता गांव में जल लाने के लिए गांव की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मुश्किल काम अब खत्म हो गया है। पहले महिलाओं को प्रतिदिन सुबह दो घंटे और शाम को दो घंटे गांव की पहाड़ी के पीछे के झरनों से पानी लाने में बिताना पड़ता था।

चूंकि गांव के ज्यादातर युवा पास के शहरों में काम करने जाते थे वृद्ध महिलाएं मवेशियों को चारा देने, घर का काम करने और खेतों में काम करने का जिम्मा उठाती थीं। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी वाले लेलता गांव के 115 परिवारों के चहरों पर मुस्कान आ गई है जिससे हिमालय घाटी के गढ़वाल पहाड़ों की सुंदरता और बढ़ गई है।

इसके लिए, वर्ष 2019 में संस्थापित पाइपड जल आपूर्ति प्रणाली का धन्यवाद। जल जीवन मिशन के कार्यकाल में प्रत्येक परिवार को नल जल कनेक्शन मिला है। अब 24 घंटे 7 दिन गांव में जल उपलब्ध है। गांव में काफी ऊचाई पर बना सामुदायिक जल भंडारण टैंक पर्याप्त प्रेशर में पानी उपलब्ध कराता है। गांव वालों ने यह सुनिश्चित किया है कि उनके छतों पर बने टैंकों में फलोट वाल्व लगा हो ताकि टैंक भरने के बाद पानी बर्बाद ना हो। उनहोंने ग्राम कार्य योजना तैयार की है और वीडब्ल्यूएससी का गठन किया है ताकि वे प्रभावी तरीके से इस प्रणाली का प्रबंधन कर सके।

आज गांव के वृद्ध जन गांव वालों के बेहतर जीवन के विषय में बात करते है जिसका वे अपने युवा वर्षों में सपना देखा करते थे। महिलाएं अब खुशी-खुशी मवेशी पालन और पास के बगीचों में खेती में हाथ बटाती हैं।

जैसा कि हम जानते है जल ही जीवन है और यदि हिमालय के पहाड़ों में आपके घरों तक पानी उपलब्ध हो तो जीवन कितना खुशहाल हो सकता है।

पंजाब में समुदाय, पेयजल प्रबंधन में नेतृत्व कर रहे हैं

होशियारपुर जिले के कंडी क्षेत्र का तखनी गांव शिवालिक पहाड़ी की घाटी में स्थित एक सुदुर गांव है जिसमें 165 परिवार हैं। पहले गांव वालों को पेयजल हेतु इस क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों और खुले कुओं पर निर्भर रहना पड़ता था। संदूषित जल के सेवन से गांव वालों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती थीं।

एक दिन गांव वालों ने पेयजल की समस्या का समाधान करने का सोचा और स्थानीय प्राधिकरण (पीएचईडी) को संपर्क किया जिसके परिणामस्वरूप जून 2020 में भू-जल आधारित एकल ग्राम परियोजना (एसवीएस) संस्थापित किया गया। तखनी एसवीएस स्कूलों और आंगनवड़ियों सहित गांव के सभी घरों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराता है। यह परियोजना पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत जल स्वच्छता समिति (जीपीडब्ल्यूएससी) द्वारा संचालित है। जीपीडब्ल्यूएससी प्रचालन एवं रख-रखाव के मासिक व्यय की पूर्ति के लिए प्रत्येक परिवार से 150 रुपए प्रति माह लेता है। इस परियोजना की एक विशेषता यह है कि इससे बहुत ऊचाई पर स्थित 40 परिवारों को जल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके लिए बूस्टर पंप के माध्यम से पानी चढ़ाया जाता है। इस परियोजना से 40 वर्षों बाद ऊचाई पर स्थित परिवारों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल मिल सका है। एफटीके का उपयोग करके समुदाय द्वारा जल गुणवत्ता की निगरानी की जाती है।

स्थानीय ग्राम समुदाय द्वारा जल जीवन मिशन की आयोजन, कार्यान्वयन और प्रचालन एवं रख-रखाव की नीति पर आधारित समुदाय द्वारा चालित एकल ग्राम जल आपूर्ति परियोजनाओं के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों में तखनी, ताना और नौलखा गांव शामिल है।

दोनों परियोजनाओं में गतिविधियों को चलाने की जिम्मेदारी जीपीडब्ल्यूएससी की 50% से अधिक महिला सदस्यों ने ली है। पंजाब के ज्यादातर गांव में जीपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से चलाई जा रही परियोजनाओं के प्रचालन एवं रख-रखाव में समुदाय सक्रिय रूप से भागीदार है। 13,690 पाइप्ड जलापूर्ति (पीडब्ल्यूएस) गांवों में से 5,624 पीडब्ल्यूएस गांव जीपीडब्ल्यूएससी द्वारा प्रबंधित है। पंजाब में जलापूर्ति परियोजनाओं के गांव के ढांचों के लिए सामुदायकि योगदान इकट्ठा करने की समरूपी नीति है। समतल स्थानों पर प्रति परिवार 800 रुपए (सामान्य वर्ग) और प्रति परिवार 400 रुपए (अनुसूचित जाति) इकट्ठा किया जाता है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा प्रति परिवार 400 रुपए (सामान्य वर्ग) और प्रति परिवार 200 रुपए (अनुसूचित जाति) इकट्ठा किया जाता है। नीति के रूप में नई जलापूर्ति का काम तभी प्रारम्भ होता है जब संपूर्ण समुदाय से योगदान इकट्ठा कर लिया गया हो और उसे जीपीडब्ल्यूएससी के बैंक खाते में जमा कर दिया गया हो।

पंजाब के ज्यादातर गांव में घरेलू स्तर पर जल मीटर लगाए गए हैं। कुछ गांवों में जल मीटर की रीडिंग के आधार पर प्रमाणात्मक शुल्क लिया जाता है। तथापि, ज्यादातर गांवों में एक निश्चित शुल्क ही लिया जाता है। जीपीडब्ल्यूएससी द्वारा चलाई जा रही ज्यादातर जलापूर्ति परियोजनाएं वित्तीय रूप से स्थाई हैं और वे घरेलू स्तर पर शुल्क लेकर संपूर्ण प्रचालन एवं रख-रखाव लागत एकत्रित कर लेते हैं। राज्य शत प्रतिशत प्रमाणात्मक शुल्क पर बल देता है ताकि पानी की कम से कम बर्बादी हो सके।

इसका लक्ष्य विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों सहित गांव वालों के जीवन को बेहतर बनाना और वर्ष 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को "कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन" (एफएचटीसी) के माध्यम से बेहतर जीवन प्रदान करना है। राज्य वर्ष 2022 तक 'हर घर जल राज्य' बनने के लिए प्रतिबद्ध है।

ओड़ीशाः पेयजल स्रोतों की जांच हेतु महिलाओं को सशक्त बनाना

यह समझना नितांत आवश्यक है कि लोगों के स्वास्थ्य और बेहतरी के लिए जल की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्षेत्र जांच किट (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय स्तर पर जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी जाती है। ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता (आरडब्ल्यूएसएण्डएस), ओड़ीशा ने 1 से 30 नवंबर, 2020 तक एक माह लंबा अभियान चलाया और स्वंय सहायता समूह (एसएचजी) के माध्यम से हैंडपंप, ट्यूबवैल/ खुदे कुएं/ नलों जैसे चार लाख पेयजल स्रोतों की जांच करवाई।

जल गुणवत्ता निगरानी और सर्वेक्षण के दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, अब यह विभागीय जिम्मेदारी न रहकर समुदाय का लोकतांत्रिक अधिकार बन गया है। इस नए दृष्टिकोण से समुदाय के साथ भागीदारी का विस्तार हुआ है और अब यह मात्र "जिम्मेदारी में परिवर्तन" नहीं रह गया है। इसने इस धारणा को बदल दिया है कि जल गुणवत्ता प्रबंधन सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी का ही कार्य क्षेत्र है बल्कि यह बताया है कि समुदाय भी उचित रीति से इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान जल स्रोतों की जांच सुनिश्चित करना विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण था। जल वारियर के रुप में कार्य करने के लिए 12 हजार स्व-रोजगार मेकैनिकों (एसईएम) और 11 हजार से अधिक स्वंय सहायता समूहों (एसएचजी) की महिला सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें 7 हजार एफटीके उपलब्ध कराया गया। आरडब्ल्यूएसएण्डएस, ओड़ीशा के राज्य जल जांच प्रयोगशाला ने ब्लॉक स्तर पर 105 प्रयोगशाला कार्मिकों और 314 कनिष्ठ अभियंताओं समेत संसाधन व्यक्तियों का एक पुल बनाया।

अभियान के लिए एसईएम और एसएचजी के मार्ग दर्शन हेतु ये संसाधन व्यक्ति उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगें।अभियान के क्षमता संवर्धन ढांचे के इस रीति से मलका नगरी, नवारंगपुर, सुन्दरगढ़ जैसे हिटलर लैण्ड के न्यूनतम साक्षर समुदायों को भी एफटीके का उपयोग करके जल स्रोतों की जांच करने में सहायता मिली है। एसएचजी सदस्यों ने समुदाय की मौजूदगी में नमूनों को इकट्ठा कर उसकी जांच की तथा यदि पेयजल स्रोत में कोई संदूषण पाया जाता है तो उसके विषय में लोगों को संवेदनशील बनाया जाता है। जिन जल नमूनों में जैविक अथवा रासायनिक संदूषण पाया जाता है उन्हें पुष्टि हेतु जिला और उप-मंडल स्तर के प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है।

स्मार्टमीटर का उपयोग करके ग्रामीण घरों में जल आपूर्ति की निगरानी

सरपंच, श्री जसपाल सिंह के लिए वह बहुत गर्व का क्षण था जब इस वर्ष डबाली गांव, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 'हर घर जल गांव' बन गया। घरों के जल उपयोग की निगरानी हेतु 145 घरेलू कनेक्शनों में जल मीटर लगाया गया। डबाली गांव पंजाब के एसएएस नगर जिले का एक छोटा कृषि संपुष्ट गांव हैं। पहले यहां के लोग जल की दैनिक आवश्यकता के लिए ट्यूबवैलों पर निर्भर करते थे। जसपाल सिंह ने पंचायत की निधियों से जल मीटर संस्थापित करने की शुरूआत की। ग्राम पंचायत जल स्वच्छता समिति (जीपीडब्ल्यूएससी) जल मीटर की रीडिग लेता है, बिल इकट्ठा करता है और जल आपूर्ति परियोजनाओं के प्रचालन एवं रख-रखाव लागत का प्रबंधन करता है। फतेहगढ़ साहिब जिले का मोहन माजरा गांव, एसएएस नगर जिले का सिंहपुर गांव, जालंधर जिले का साहपुर गांव, ऐसे कुछ उदाहरणीय जीपीडब्ल्यूएससी हैं जो सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध कराए गए जलापूर्ति का जल बिल इकट्ठा करने के लिए जल मीटर स्थापित करने की शुरूआत कर चैंपियन बन गए हैं ताकि प्रचालन एवं रख-रखाव लागत की व्यवस्था की जा सके और समुदायों में स्वामित्व का विकास हो सके।

पंजाब राज्य, जल मीटर की स्थापना करके घरेलू स्तर पर जल उपयोग की निगरानी करने वाले राज्यों में अग्रणी बन गया है। मीटर लगाना और उसका बिल इकट्ठा करने से लोगों को पानी की बचत, लिकेज दूर करने और बर्बादी को रोकने के लिए बढ़ावा भी मिलता है।

90% उपभोक्ताओं नें अपने घरों में स्मार्ट जल मीटर लगा लिया है और वे नियमित रूप से जल शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। जल उपभोग की निगरानी और उसके भुगतान में जल मीटर मदद करता है। इससे भू-जल संरक्षण और समुदाय में समानता की भावना बढ़ाने में मदद मिलती है।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग (डीडब्ल्यूएसएस), पंजाब ने मोहाली जिले के 35 गांवों के घरेलू नल कनेक्शनों में मुफ्त में जल मीटर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। प्रारंभिक परियोजना के रूप में ग्रामीण समुदाय को उनके अपने जल आपूर्ति प्रणालियों के निर्माण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बनाने, जल की बर्बादी को रोकने, प्रणाली को वित्तीय रूप से स्थायी बनाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता-पूर्ण सेवा देने के उद्देश्य से 7,899 जल मीटर संस्थापित किया गया है ताकि जल आपूर्ति परियोजनाओं के प्रचालन एवं रख-रखाव हेतु परिमाणात्मक आधार पर जल शुल्क लिया जा सके।

वर्तमान में, 609 गांवों में घरेलू स्तर पर जल मीटर लगाए गए हैं। विभाग द्वारा गांव में आपूर्तित जल की मात्रा को मापने के लिए स्रोत पर भी बल्क जल मीटर लगाया गया है। लाभार्थी स्तर पर स्रोत और उपभोग की निगरानी करके प्रणाली में हो रहे किसी लीकेज, अनधिकृत जल कनेक्शन का आसानी से पता लगाया जा सकता है। मजदूरी सहित 1800 से 2000 रुपए प्रति मीटर के औसत लागत पर दो प्रकार के जल मीटर यथा मल्टीजैक और मैगनेटिक ट्रान्समिशन, संस्थापित किए जा रहे हैं।

जल मीटर लगाने से पेयजल के असमान वितरण और जल की बर्बादी के मुद्दे को निपटाया जा सकता है और जीपीडब्ल्यूएससी प्रचालन एवं रख-रखाव लागत जुटा सकता है। इन-फ्लो और आउट-फ्लो को माप कर प्रणाली की जल लेखा-परीक्षा संभव हो गई है। इसके साथ ही सभी परिवारों को समान रूप से जल उपलब्ध कराने से समुदाय का संतुष्टि स्तर भी बढ़ गया है।

तमिलनाडु के वल्लम गांव के पंप ऑपरेटर का जीवन

- रचना गहिलोत बिष्ट

48 वर्षीय वृद्ध और 2 बच्चों की मां श्रीमती जी.कला, वेल्लोर जिले के वल्लम गांव की एकमात्र महिला पंप ऑपरेटर है। पंप ऑपरेटर और तकनीशियन के रूप में उनकी यात्रा 9 वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह वह समय था जब उनका परिवार उनके पति के नजदीकी मित्र जिसकी भागीदारी में वे काम करते थे, के निधन से शोकाकुल था। उनका मित्र कुल्लाथूमेडा बस्ती में पंप ऑपरेटर था। उसके निधन से पंप के प्रचालन का कार्य रूक गया। गांव में इस कार्य को करने वाला कोई भी कुशल व्यक्ति नहीं था। दुखी होने के बावजूद कला आगे आई। अब तक वे अपने पति के साथ ही केवल मजदूरी का काम करती थी। उन्होंने अपना नाम पंप ऑपरेटर के लिए सामने रखा। विभाग ने उनको बढ़ावा देते हुए उन्हें पंप के प्रचालन हेतु मूलभूत प्रशिक्षण दिया। कला ने जिले में एक महिला पप ऑपरेटर के रूप में पुरूष वर्चस्व जगत के रिक्त पद को भरा और तीन ओवरहैड टैंक (ओएचटी) का प्रचालन करने लगी।

जी.कला गौरव से 475 परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं, जिसमें 28.6% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन हैं। प्रत्येक परिवार तक पीने योग्य जल पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। एक नया बोरवैल खोदा गया है और संपूर्ण गांव को जनवरी, 2021 तक "हर घर जल" उपलब्ध कराने की योजना है।

कला स्वप्रेरित महिला हैं जिन्होंने समय के साथ छोटे-मोटे मरम्मत करने का कौशल भी सीख लिया है। इन वर्षों में उन्हें समुदाय से सम्मान मिला है और पाइप लाइन में किसी भी प्रकार के लिकेज होने पर वे मदद के लिए अवश्य जाती हैं। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत, निर्माण कार्य की निगरानी करके और मौजूदा पाइप लाइन अथवा अपेक्षित नए पाइप लाइन के स्थान के मानचित्रण में सहायता देकर वे लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में भी सहायता देती हैं। यदि जी.कला कोई लिकेज देखती हैं तो वे अपने खुद की निधियों से 500 रुपए तक खर्च करके उसकी मरम्मत करती हैं। बाद में, पंचायत द्वारा उन्हें इस राशि की प्रतिपूर्ति मिल जाती है। कला के अनुरोध पर मजदूर और पलंबर भी जल्दी आते हैं। गांव वाले गांव में जी.कला के होने से बहुत खश हैं, जो सिर्फ फोन करने पर आ जाती हैं। जी.कला चाहती हैं कि और महिलाएं सामने आएं और मैकेनिक तथा पंप ऑपरेटर जैसे पेशे को अपनाएं। "यह केलव पुरूषों का कार्य नहीं है। महिलाएं ही जल की अनुपलब्धता से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। यदि हम अन्य कार्य कर सकते हैं तो कोई कौशल का कार्य क्यों नहीं। मैंने इस पेशे में लोगों का प्यार और सम्मान अर्जित किया है।"

पीएचईडी के अधिकारी गांव में एसएचजी को कौशल प्रशिक्षण देने की योजना बना रहे हैं ताकि सृजित अवसंरचनाओं को स्थायी बनाने में सहायता मिले और हर घर जल कार्यक्रम अधिक समेकित बन सके।

90 परिवारों सहित रानीपेट जिले का कनिकापुरम गांव जल जीवन मिशन के हर घर जल कार्यक्रम के अंतर्गत शत प्रतिशत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्टीविटी प्राप्त कर चुका है। 24 वर्षीय भाग्य लक्ष्मी अपने घर में पीने योग्य नल कनेक्शन प्राप्त करके बहुत खुश है। संजीव के साथ विवाह के उपरांत वे इस गांव में रहने आई थी।

विवाह के बाद, पिछले तीन वर्षों से वे जल संकट से जुझ रही थी। प्रतिदिन वे जल की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए पीने, खाना पकाने, स्नान, धुलाई और सफाई के लिए 20 बार स्टैण्डपोस्ट पर आती-जाती हैं।

एफएचटीसी से तमिलनाडु के ग्रामीण परिवारों के जिलों में मुस्कान और राहत आ गया है

भाग्य लक्ष्मी और उसके परिवार के सदस्य खुश हैं क्योंकि अब गर्भ से होने के कारण उसे भारी सामान नहीं उठाना है। "चूंकि शादी के तीन वर्ष बाद मैं पहली बार गर्भ से हूँ परिवार मेरा अत्यधिक ख्याल रख रहा है। जब मुझे इसके बारे में पता लगा तब मैं पांच किलो भार तक उठाने में डरती थी परन्तु अब सरकार मेरी रक्षक बनकर सामने आई है। अब मैं आराम से अपने ससुराल में गर्भ के आखिरी दिनों तक रह सकती हूँ।" मेरे पति ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का हिस्सा है। मेरी शारीरिक स्थिति के विषय में जानकर उन्होंने घर तक जल लाने का प्रयास किया और यह सुनिश्चित किया कि मुझे और मेरी बुढ़ी सास का जीवन आसान हो सके। जल जीवन मिशन से भाग्य लक्ष्मी जैसे हजारों परिवारों को खुशियां मिली हैं।

असम की ओक्किबुरवा सखिया एक अग्रणी उदाहरण

हम सभी समाज की भलाई के लिए काम करने की बात करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हैं श्रीमती ओक्किबुरवा सखिया जो असम के शांतिपुर गाँव की रहने वाली हैं। सालों तक, उन्होंने अपने गाँव में नल द्वारा जल की आपूर्ति सहित बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी को संघर्ष करते देखा था। पानी लाने के लिए उन्हें झरने तक जाना पड़ता था।

आशा की किरण तब उभरी जब सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग ने नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए उनके गाँव का दौरा किया। अधिकारी जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए भूमि की तलाश में गए, लेकिन उन्हें ऐसा स्थान नहीं मिला, जो इस उद्देश्य की पूर्ति करता हो। जब आशा की किरण धूमिल होना शुरू हो गई तब ओक्किबुरवा सखिया ने समाज की भलाई के लिए 2 एकड़ जमीन दान करने का फैसला किया। उन्होंने अधिकारियों को अपनी भूमि पर जल आपूर्ति प्रणाली स्थापित करने की पेशकश की जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हर घर तक पाइप से जलापूर्ति पहुंचे। वर्तमान में, 85 घरों में पीने का पानी मिल रहा है और यह योजना है कि शेष 125 घरों में जल्द ही जल जीवन मिशन के तहत नल जल कनेक्शन मिलेगा। ओक्किबुरवा सखिया द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर, अब समुदाय पाइपगत जल के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में 50/- रुपये अदा करने पर सहमत हो गया है। सभी भुगतान विवरणों के साथ एक उचित खाता बही बनाई गई है। 10% लेट फीस चार्ज वसूला जा रहा है।

जेजेएम से आई बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के गाँवों में खुशियाँ

- देविना श्रीवास्तव

उत्तर प्रदेश के जिला चित्रकूट के गाँव हन्ना बिनैका के इन बच्चों की आकर्षक मुस्कान और नज़रों में चमक साफ दिखाई देती है। यह गांव जल संकट-ग्रस्त बुंदेलखंड इलाके की हनुमान गंज बस्ती है। उनके लिए मामूली परवरिश और सीमित साधन उच्च लक्ष्य में कोई बाधा नहीं है। कुछ महीने पहले तक इन बच्चों को स्कूल के समय से समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता था क्योंकि वे घर के कामों का बोझ साझा कर रहे थे, इस तरह उन्हें एक दिन में हैंडपंप से पानी लाने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब तीन महीनों में गांव में काफी बदलाव आया है। हर घर में नल जल कनेक्शन की उपलब्धता के साथ, ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में कई गुना सुधार हुआ है।

एक 8 साल का ग्रामीण लड़का मंद मुस्कुराहट के साथ कहता है - *"अब मुझे स्कूल में देरी से पहुँचने के लिए अपने शिक्षक से डांट नहीं पड़ती है।"* उसकी मासूमियत आपके दिल को छूती है और आपको इस क्षेत्र के निवासियों के दैनिक जीवन में पानी की कमी और उसके प्रभाव पर गहराई से विचार करने को प्रेरित करती है। बच्चों को अब खेलने और अध्ययन करने के लिए अधिक समय मिल रहा है।

पहले स्कूल और आंगनवाड़ी में पीने के पानी की कमी ने उनके सीखने के माहौल को प्रभावित किया था, लेकिन अब स्कूल और आंगनवाड़ी में नल कनेक्शन के माध्यम से साफ पीने योग्य पानी छात्रों और शिक्षकों दोनों को बेहतर माहौल प्रदान कर रहा है।

हर घर में नल का जल कनेक्शन उपलब्ध होने से गाँव की महिलाओं को सबसे अधिक फायदा हुआ है। क्योंकि महिलाएं आमतौर पर अपने परिवारों के लिए जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी के बोझ से चिंताग्रस्त रहती हैं, यह चिंता उनके स्वास्थ्य, शारीरिक मुद्रा और आपसी रिश्तों को मजबूत करने के समय पर बुरा असर डालती है। हीरामनी, 40 साल से अधिक आयु की एक महिला अपने घर पर नल के पानी की व्यवस्था होने से बेहद खुश और संतुष्ट है। उसके स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ है और अब उसके पास आराम के लिए अधिक समय है। इसी तरह, इस गाँव की कई महिलाएँ घर पर स्वच्छ पानी के आने से मिलने वाले नए आराम का आनंद ले रही हैं। राम सवई, एक अन्य महिला को भी आराम है क्योंकि उसे लगता है कि उसके बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है - जल जीवन मिशन के तहत घर में साफ पानी के लिए सभी का धन्यवाद। गाँव हन्ना बिनैका में 632 घर हैं और अब 100% एमएचटीसी कवरेज है, यहाँ स्कूलों और आंगनवाड़ी में भी नल जल कनेक्शन उपलब्ध है।

यहां नई योजना का निर्माण 203.89 लाख रुपये की लागत से किया गया है जिसमें 200 केएल क्षमता से अधिक हेड टैंक (ओएचटी)/लगभग 10.46 किमी जीआई/डीआई संवितरण नेटवर्क शामिल है। हनुमान गंज बसावट में एक और गांव लौरी जिला चित्रकूट ने 100% एफएचटीसी का दर्जा प्राप्त किया है। जल जीवन मिशन के तहत गांव में 183 घरों में नल जल कनेक्शन है। जैसे ही आप गाँव में प्रवेश करते हैं, घरों की साफ-सुथरी पंक्तियाँ, बिजली के साथ रसोई गैस की आपूर्ति और अब नल जल कनेक्शन बहुत अच्छी तरह से ग्रामीणों की उन्नत जीवन शैली की व्याख्या करता है। यहाँ के निवासियों को लगता है कि जल जीवन मिशन के माध्यम से नल कनेक्शनों के प्रावधान ने उस टूटी हुई कड़ी को जोड़ दिया है जो गाँव के समग्र विकास के लिए आवश्यक थी।

जल जीवन मिशन के लिए पुनः इंजीनियरिंग

- वीके माधवन , मुख्य कार्यकारी वाटर ऐड इंडिया

"हर घर संचालन और रखरखाव की लागत को कवर करने के लिए प्रति माह बानवे रुपये का भुगतान करेगा"। मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के धबोती गाँव की ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के एक सदस्य के इस कथन ने मुझे वाकई ही विचलित कर दिया। यहाँ मैं उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहा था जिसके द्वारा उन्होंने अपनी ग्राम कार्य योजना (वीएपी) बनाई थी, लेकिन इस समिति ने वार्षिक आधार पर संचालन और रखरखाव की लागत और प्रति घर की लागत की भी गणना की थी। योजना के कार्यान्वयन से पहले ही सभी शुरू हो गए थे। वे सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) द्वारा लागत अनुमान सहित बनाई गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से परिचित थे।

टांडा खेड़ा दसई, धार जिले में गर्मियों के महीनों में पानी की उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता और महिलाओं पर पानी भरने पर बोझ स्पष्ट था। पूरे वर्ष भर उनके घर पर पानी, उनके जीवन और स्वास्थ्य को काफी बदल सकता है, और फलस्वरूप प्रत्याशा की श्रेष्ठ भावना मूर्त थी। उन्होंने अपनी योजना के लिए पानी के स्रोत के रूप में एक कुएं की पहचान की थी। हालांकि घरों के पास बोर-वेल होने की संभावना मौजूद थी, फिर भी उन्होंने अपने स्रोत के रूप में कुएं की पहचान की थी। मेरी जिज्ञासा बढ़ी और हमने इस कुएँ का दौरा किया। खूबसूरती से अवस्थित, एक बड़े मिट्टी के बांध से ठीक आगे और नीचे पानी से भरा हुआ तथा उसे कई दिशाओं से पानी स्पष्ट रूप से प्राप्त हो रहा था।

ग्रामीणों की बात सुनने और उनको अपनी जरूरतों के लिए योजना बनाने की अनुमति देने में ही समझदारी थी। दोनों उदाहरणों में, यह स्पष्ट था कि ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) सक्रिय थी और उनकी योजना भागीदारी प्रक्रियाओं का परिणाम थी। हालाँकि, पीएचईडी की सहायता और भागीदारी तथा गैर-लाभकारी संगठनों की भूमिका (सीहोर में समर्थन और धार में उन्नत अनुसंधान और विकास केंद्र) और उनके समन्वित प्रयास स्पष्ट थे। मध्यप्रदेश को उम्मीद है कि जनवरी 2021 के मध्य तक इसी तरह की भूमिका निभाने के लिए समर्थन एजेंसियां (आईएसए) मौजूद होंगी। वीडब्ल्यूएससी जल जीवन मिशन की सफलता के लिए केंद्रीय हैं और गाँव की कार्य योजना उनकी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। चूंकि इन समितियों को अपनी जल योजनाओं का प्रबंधन करना चाहिए, इसलिए डिजाइन, बजट और योजना के लिए अनिवार्यताएं अलग-अलग होनी चाहिए।

यदि किसी योजना की लागत अधिक है, तो ग्रामीणों को अधिक योगदान देना होगा। यदि यह योजना जटिल है, तो बाद में इसमें प्रबंधन की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसे हर घर में पानी उपलब्ध कराने के लिए एक इंजीनियरिंग चुनौती के रूप में ही सोचना पर्याप्त नहीं है - यह आसान भाग है। प्रक्रिया के हर चरण का मार्गदर्शन करने वाले प्राथमिक प्रश्न हैं - क्या यह वीडब्ल्यूएससी को मजबूत और सशक्त करेगा और क्या इससे उनके लिए काम करना और उसे बनाए रखना आसान हो जाएगा। पीएचईडी और आईएसए के सामने चुनौती केवल एक योजना को लागू करने या एक योजना के निर्माण को सुविधाजनक बनाने मात्र ही नहीं है। संस्थागत क्षमता में निवेश के बिना बुनियादी ढांचे में निवेश विफल हो जाएगा। चुनौती यह है कि हर गाँव में जीवंत संस्थाएँ बनाने में मदद की जाए, जो पूरे साल भर हर घर में पानी पहुँचाने के लिए अपनी पेयजल व्यवस्था की योजनाएं, डिज़ाइन तैयार कर सकें उनके स्वामित्व का भार ले और उनका प्रबंधन कर सकें।

क्षेत्र से कार्य

भारत

जल जीवन मिशन (जेजेएम)
क्षेत्रीय जिला दौरा मानचित्र

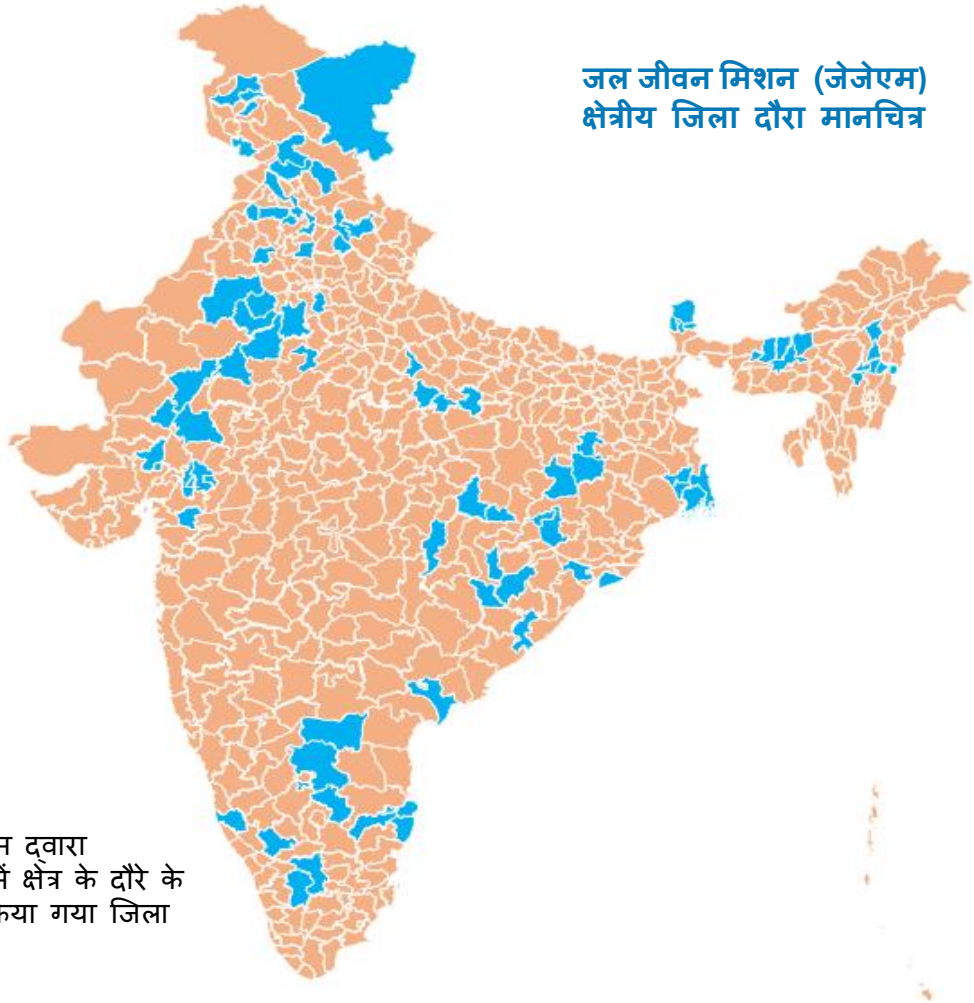

एनजेजेएम टीम द्वारा दिसंबर, 2020 में क्षेत्र के दौरे के दौरान कवर किया गया जिला

असम का दौरा

राष्ट्रीय जेजेएम की तीन टीमों ने 13-17 दिसंबर, 2020 तक सात जिलों कामरूप, जोरहाट, माजुली, नलबाड़ी, दरांग, बोंगईगांव और बारापेता के 47 गांवों को कवर करते हुए असम राज्य का दौरा किया।

असम ने कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है जो उल्लेख लायक हैं जैसेकि ऊर्जा को संरक्षित करने के साधन के रूप में और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए डीजल/विद्युत आधारित मोटरों से सौर ऊर्जा आधारित प्रणालियां। माजुली में, उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह किया जा रहा है जिससे पानी की आपूर्ति प्रणाली के संचालन एवं रखरखाव में मदद मिलती है। फील्ड टेस्ट किटों के माध्यम से पानी का परीक्षण करने के लिए 5 महिला सदस्यों की एक टीम बनाई गई है। महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि परीक्षण के परिणाम सटीक और विश्वसनीय हों। कुछ गांवों में समुदाय जल आपूर्ति कार्यक्रम की सहायता के साधन के रूप में भूमि दान करने को तैयार हैं। भूमि ज्यादातर पंप हाउस की स्थापना के लिए और भूजल के संदूषण की जांच करने के लिए व्यक्तिगत निधियों से एफएचटीसी कनेक्शन के आसपास प्लेटफार्म बनाने के लिए आवश्यक है। निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में गति सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा एफएचटीसी के मौजूदा ढ़ांचे में फेरबदल कर सही करने का काम किया जा रहा है।

हरियाणा

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीम ने 10-12 नवंबर, 2020 के दौरान हरियाणा के छह जिलों अर्थात फरीदाबाद, पलवल, मेवात, करनाल, अंबाला और पंचकुला का दौरा किया। वर्तमान में, 65% घरों में राज्य में कार्यशील नल जल कनेक्शन (एफएचटीसी) हैं। वर्ष 2022 तक 100% एफएचटीसी कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 31.05 लाख परिवारों को एफएचटीसी प्रदान किया जाना है। राज्य में पीएचईडी ने जल जीवन मिशन के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार योजना के तहत की गई प्रगति की नियमित निगरानी करने के लिए एक समर्पित ग्रामीण जल डैशबोर्ड विकसित किया है। मेवात में कुल घुलित ठोस (टीडीएस) की समस्या कम करने के लिए, जलभृत को रिचार्ज करने के लिए नवीन वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित की गई है।

आंध्र प्रदेश

अनतपुर जिले में मुस्तुर ग्राम पंचायत के राघवपल्ली गांव की जयम्मा नल कनेक्शन मिलने से खुश है क्योंकि इससे उनके जीवन में सुधार हुआ है।

कुरनूल जिले के वड्डामेनु गांव में लोगों को प्रतिदिन छह घंटे पानी की आपूर्ति मिलती है। ग्रामीण पीने के अलावा अन्य सभी उद्देश्यों के लिए नल के पानी का उपयोग करते हैं क्योंकि वे हैंड पंप से निकाले गए पानी का स्वाद पसंद करते हैं। विजयनगरम जिले में रीमापेटा ग्राम पंचायत में 100% एफएचटीसी प्रदान किए गये हैं। जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ग्राम जल और स्वच्छता समिति का गठन करने में 50% महिलाओं की भागीदारी के नियम का पालन किया गया है। वीडब्ल्यूएससी सदस्य पानी का नियमित क्लोरीनीकरण सुनिश्चित करते हैं।

श्रीमती साई देवी कहती हैं कि *"हर घर में नल कनेक्शन लग जाने से हमें स्थानीय चिकित्सक के पास जाने की जरूरत काफी कम पड़ती है। आंगनवाड़ियों, जहां शिशु कोविड के दौरान आते हैं, में पीने योग्य पानी का कनेक्शन लग जाने से, सब एडब्ल्यूएससी में साफ पानी मिल रहा है जो हम सभी के लिए एक वरदान है।"* संपत्ति कर के हिस्से के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा ओ एंड एम शुल्क एकत्र किया जा रहा है। हर घर में 55 इपीसीडी पानी दिया जाता है। अनंदपुरम जिले की मर्दडु ग्राम पंचायत के एस. बंदियापल्ले गांव की कुल जनसंख्या 572 है और कुल 147 परिवार हैं। यह फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र है। भूजल पीने के लायक नहीं है। सत्य साई ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत चित्रावती बैलेंसिंग जलाशय से उपचारित सतही जल की गाँव में आपूर्ति की जाती है। जबकि 40 घरों में एफएचटीसी है, शेष 107 में अस्थायी गैर-नियमित नल कनेक्शन हैं।

भार्गवी एक युवा है। वह स्नातक के द्वितीय वर्ष की छात्रा है और एक वीडब्ल्यूएससी सदस्य है। वह कहती है कि "हमारे घरों में नल कनेक्शन लग जाने के बाद से हमारा जीवन आसान हो गया है। अब हम अध्ययन और अन्य गतिविधियां करने के लिए समय मिलता है।

रहने वाली आर. लीलावाटम्मा और वृद्ध महिला ने कहा, *"मेरी उम्र में हर दिन सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट से पानी लेने जाना बहुत मुश्किल कार्य है। फिर भी, मुझे अपनी दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसा करना पड़ा लेकिन घर में नल कनेक्शन की सुविधा प्राप्त हो जाने से, मैं अब राहत महसूस करती हूं। कम से कम बुढ़ापे में मुझे भारी बाल्टियां उठाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। पानी के प्रवाह को देखकर मुझे वास्तव में बहुत खुशी होती है।"*

कर्नाटक

कर्नाटक ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रभाग ने 'परिहार' नामक एक ऑनलाइन शिकायत निवारण डैशबोर्ड शुरू किया है। यह पानी संबंधी मुद्दों का प्रबंधन करने के लिए एक प्रभावी और कुशल तरीका है।

समयबद्ध तरीके से सुधार के लिए शिकायत सीधे एसएमएस के माध्यम से संबंधित अधिकारी के पास जाती है। अगर किसी निश्चित समय सीमा के भीतर मामले को हल नहीं किया जाता है, तो शिकायत स्वचालित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी जाती है। डैशबोर्ड विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण को दर्शाता है।

कर्नाटक सरकार द्वारा एक सामुदायिक प्रबंधित उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है जिसमें स्मार्ट कार्ड रिचार्ज की सुविधा है। 20 लीटर पानी के लिए 2/- रु से 5/- रु तक की दर से। परिवार जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुरूप संचालन एवं रखरखाव के लिए 50/- रुपये से 100/- रुपये तक का भुगतान उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में अदा करते हैं।

कर्नाटक में प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल स्रोत और संवितरण प्वाइंट पर नियमित जल परीक्षण करने के लिए एक फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध है। जनता के लिए अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए एक केंद्रीकृत हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है। शिकायत की स्थिति की सूचना शिकायतकर्ता को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। विकेंद्रीकृत समुदाय प्रबंधित आरओ ट्रीटमेंट प्लांट गंडमनगनेहल्ली में स्थापित किया गया है, जहां स्वचालित स्मार्ट वाटर एटीएम के माध्यम से 24 x 7 साफ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। समुदाय एक मोबाइल ऐप के माध्यम से स्मार्ट वॉटर कार्ड रिचार्ज कर सकता है।

झारखंड

एनजेजेएम की टीम ने 2-5 दिसंबर, 2020 के दौरान झारखंड में तीन जिलों नामत: गुमला, रांची और हजारीबाग का दौरा किया। उन्होंने सौर ऊर्जा के माध्यम से उपलब्ध कराई गई एकल-गाँव योजना, बहु-गाँव योजना और एफएचटीसी को कवर करते हुए 14 गाँवों का दौरा किया। झारखंड में, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1350 महिलाओं का एक समूह विकसित किया गया था, जिसे 'जलाशय' कहा जाता था, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी शौचालय निर्माण और शौचालय के नियमित उपयोग के लिए समुदाय को प्रेरित करना था। अब इन 'जलाशय' समूह को इंजीनियरिंग विभाग के साथ जोड़ दिया गया है। जैसा कि उनके पास अच्छे सामुदायिक संपर्क हैं, उनका उपयोग कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने, लोगों को पानी के लिए नल कनेक्शन हेतु प्रोत्साहित करने और उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जा रहा है।

तमिलनाडु

तमिलनाडु का लक्ष्य 2023 तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने का है और 2020-21 तक 33.94 लाख घरों को कवर करने का उद्देश्य निर्धारित है। 13-16 दिसम्बर, 2020 के दौरान, दो सदस्यों वाली तीन टीमों ने कांचीपुरम, त्रिवल्लुर, कोयंबटूर, इरोड, तिरुपूर, वेल्लोर और रानीपेट का दौरा किया।

लोग रोज़ाना सुबह 2 घंटे पानी की पर्याप्त आपूर्ति के साथ कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन मिलने से खुश थे। यह देखा गया है कि महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व के साथ 10 सदस्यी ग्राम जल और स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। सभी जिलों के स्कूलों और आंगनवाड़ी में नल जल कनेक्शन था। जल गुणवत्ता निगरानी के लिए 5 सदस्यों की एक टीम का चयन किया गया है। के तहत इनकी योजना तैयार की गई है।

पंप ऑपरेटरों को नियुक्त किया गया है और जल शुल्क के प्रति उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में घरों से 30/- रुपये प्रति माह संगृहीत किए जाते हैं। टीडब्ल्यूएडी बोर्ड मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों में फेरबदल कर उन्हें दुरस्त करने का काम करेंगे, ताकि प्रगति तेज हो सके। शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है और कुछ स्थानों पर पानी से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक टोल फ्री नंबर प्रदान किया गया है। स्वयं सहायता समूहों को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। सोख गड्ढे मौजूद हैं या एसबीएम-जी और पीआर को 15 वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत ग्रे वाटर मैनेजमेंट के तहत इनकी योजना तैयार की गई है।

जल परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं लेकिन दरों को मानकीकृत करने की आवश्यकता है। हर रोज औसतन पानी के 10 नमूनों का परीक्षण किया जाता है। प्रयोगशालाएं 16 रासायनिक मापदंडों और संपूर्ण जैविक प्रदूषण के लिए परीक्षण कर सकती हैं। राज्य 11 मापदंडों के तहत एनएबीएल मान्यता की मांग कर रहा है।

पश्चिम बंगाल

एनजेजेएम की एक टीम ने जेजेएम के कार्यान्वयन को देखने के लिए 2 से 5 दिसंबर, 2020 तक राज्य का दौरा किया। 4 जिलों नामत: हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में चल रही योजनाओं का दौरा किया गया। यह देख कर अच्छा लगा कि साइट पर काम अच्छी गति से हो रहा था। पश्चिम बंगाल में एक और अवलोकन यह था कि एफएचटीसी का सत्यापन लगभग साथ-साथ हो रहा था और यह एफएचटीसी प्रदान करने की एक सच्ची और वास्तविक तस्वीर दर्शाता है। इस प्रणाली में एफएचटीसी को सत्यापित करने के कार्य में लगी एजेंसी 2 दिनों के भीतर घर के मुखिया के आधार या किसी अन्य फोटो आईडी (वोटर आईडी) को जोड़कर ऐसा करती है और यह डाटा पश्चिम बंगाल पीएचई ऐप जल स्वप्न पर अपडेट किया जाता है।

डैशबोर्ड में मासिक प्रगति के संदर्भ में उपलब्ध एफएचटीसी की संख्या में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों का भी उल्लेख है।

प्रधानमंत्री ने कच्छ के मांडवी में 100 एमएलडी विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी की उपस्थिति में 15 **दिसंबर**, 2020 को गुजरात में अ-लवणीकरण संयंत्र और एक अक्षय ऊर्जा पार्क का अनावरण किया।

प्रधानमंत्री ने मांडवी कच्छ में 100 एमएलडी विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन किया, जिससे मुंद्रा, लखपत, अब्दसा और नखतारण तालुका क्षेत्र के 8 लाख लोग लाभान्वित हुए। संयंत्र से विलवणीकरण किए गए अधिशेष जल को भचाऊ, रापर और गांधीधाम के ऊपरी इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ भी साझा किया जाएगा।

कच्छ के विघकोट गाँव के पास हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क देश का सबसे बड़ा पार्क है जो 30 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करेगा और यह 72,600 हेक्टेयर में फैला हुआ है। पार्क में पवन और सौर ऊर्जा के भंडारण के लिए एक समर्पित क्षेत्र है। परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा,

"ये परियोजनाएं आदिवासियों, किसानों, पशुपालकों और क्षेत्र के आम लोगों को एकत्रित करेंगी। कच्छ देश के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। गुजरात सरकार ने पिछले बीस वर्षों में कई किसान हितैषी जल योजनाएं शुरू की हैं..."

नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

"कैच द रेन" जागरूकता प्रसार अभियान का शुभारंभ

"कैच द रेन" एक जागरूकता अभियान है जिसका शुभारंभ श्री रतन लाल कटारिया, जल शक्ति और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री की उपस्थिति में श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री और श्री किरेन रिजिजू, युवा मामलों और खेल तथा अल्पसंख्यक कार्य के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसमें देश भर के 623 जिलों को कवर किया गया है।

इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संबंधी एकीकृत जल प्रबंधन अवधारणा से युवाओं को जोड़ना है। यह चार माह का अभियान दिसंबर के मध्य में शुरू किया और मार्च 2021 तक जारी रहेगा। जल संरक्षण के बारे में जागरूकता का प्रसार बड़े सामूहिक जागरूकता अभियानों, दीवार लेखन, बैनर, ई-पोस्टर, ज्ञान प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटकों और आईईसी सामग्री के माध्यम से किया जाएगा। इस अभियान में जिला प्रशासन, लाइन विभाग, जल एजेंसियां, पीआरआई सदस्य, स्थानीय प्रभावक और स्वयंसेवक शामिल हैं।

अभियान के लिए उपयोग की जाने वाली टैग लाइन है "कैच द रेन, वेयर इट फाल्स, वैन इट फाल्स" ताकि हितधारक विशेष रूप से मानसून के मौसम में बारिश के पानी को संगृहीत करने के लिए जलवायु परिस्थितियों और उप-मृदा स्तर के लिए उपयुक्त वर्षा जल संरक्षण संरचना विकसित करें। राज्य और जिला प्रशासन जल संचयन गड्ढों, छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली, चेक डैम, अतिक्रमण हटाने, भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए टैंक की गाद हटाने, जलग्रहण क्षेत्रों से पानी लाने के लिए चैनलों में रुकावट को दूर करने, सीढ़ीयुक्त-कुओं जैसी पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं की मरम्मत करने, जलभृतों में जल वापस भरने के लिए अकार्यशील बोरवेल और पुराने कुओं का उपयोग करने जैसे कार्य करेगा। मंत्रालयों ने प्रभावी अभियान और आईईसी गतिविधि के लिए जमीनी स्तर से जुड़ने के साधन के रूप में नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ सहबद्धता की है।

पश्चिम बंगाल के फरक्का में केंद्रीय मंत्री द्वारा "प्रयागराज में मिशन हिलसा" का शुभारंभ

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, मंत्री जल शक्ति, भारत सरकार और सचिव श्री यूपी सिंह ने 18 दिसंबर, 2020 को फरक्का , पश्चिम बंगाल में हिलसा पशुपालन स्टेशन आईसीएआर-सेंट्रल इनलैंड मत्स्य अनुसंधान संस्थान का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर समृति के रूप में फरक्का में गंगा नदी में चिह्नित हिलसा को छोड़ा।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रम के तहत संस्थान ने "प्रयागराज में मिशन हिलसा" की शुरुआत की है जिसमें 2020-23 के दौरान गंगा नदी के मध्य प्रसार भाग में 30,000 हिलसा वयस्क हिलसा पालने का लक्ष्य है। 2020-21 के दौरान, 205 ग्राम के औसत वजन वाली 5082 वयस्क हिलसा का फरक्का बैराज, पश्चिम बंगाल के धारा प्रतिकूल प्रवाह में पशुपालन किया गया है। संस्थान ने हिलसा मछली पालन की पुन:स्थापना के लिए प्रमुखतया प्रयागराज से फरक्का के बीच गंगा नदी के मध्य प्रसार भाग में हिलसा पशुपालन की पहल की है ताकि मछुआरों की आजीविका में सुधार लाया जा सके।

कोलकाता में आगामी संस्थान के लिए केंद्रीय मंत्री का दौरा

जल शक्ति के केंद्रीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कोलकाता में आगामी सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संस्थान की प्रगति की समीक्षा की।यह संस्थान सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरों की क्षमता के निर्माण में ज्ञान और सहायता प्रदान करेगा, जिससे हर घर में पीने योग्य पानी की पाइपगत जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। यह संस्थान नवाचार को बढ़ावा देगा और अन्य

प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ साझेदारी करके जल क्षेत्र में नई तकनीकों के विकास में मदद करेगा और उत्कृष्टता केंद्र के रूप में काम करेगा।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा हितधारकों के साथ संवाद

'जल जीवन संवाद' की सतत श्रृंखला में, राज्य, जिला और उप जिला अधिकारियों के लिए **गांवों में पाइपगत जलापूर्ति के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक उपयोगिता के रूप जीपीएस/वीडब्ल्यूएससी** संबंधी एक वेबिनार का आयोजन 12 दिसंबर, 2020 को किया गया था और राज्य, जिला, ब्लॉक और जीपी स्तर पर ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसका भलीभांति लाभ उठाया और इसे काफी सराहा गया। इस वेबिनार को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी प्रसारित किया गया। इस वेबिनार में लंबी अवधि तक पानी की आपूर्ति की व्यवस्था बनाए रखना और ग्राम पंचायतों की उप-समिति के रूप में वीडब्ल्यूएससी/पानी समितियों के गठन पर जीपी की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई। वीएपी तैयार करना, आईएसए की भूमिका और जिम्मेदारी तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं के रूप में वीडब्ल्यूएससी को बनाए रखना वेबिनार में चर्चा किए गए कुछ अन्य प्रमुख विषय थे।

श्री भरत लाल ने अपने मुख्य भाषण में, पेयजल स्रोतों के सुदृढ़ीकरण, पानी की आपूर्ति, ग्रे पानी के पुन:उपयोग और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर हर घर को पाइपगत पानी के लिए ओ एंड एम के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई। इस आयोजन में अन्य वक्ता थे - श्री अजीत कुमार जैन, निदेशक- सेंटर फॉर सस्टेनेबल गवर्नेंस, श्री मनीष वासुजा, वाश स्पेशलिस्ट-यूनिसेफ और श्री लीबी जॉनसन, कार्यकारी निदेशक- ग्राम विकास ट्रस्ट, ओडिशा।

"अभियांत्रिकी के सिद्धांत और हर घर को पीने योग्य पानी की आश्वासित आपूर्ति के डिजाइन" के संबंध में एक अन्य जल जीवन संवाद 19 दिसंबर, 2020 को आयोजित किया गया।

मुख्य नोट में, श्री भरत लाल, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य/आरडब्ल्यूएस इंजीनियरों को एनजेजेएम द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण/परिवर्तन प्रबंधन का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए क्षमता निर्माण हेतु जल उपयोगिताओं के रूप में कार्य करने और 'सेवा सुपुर्दगी' अवधारणा अपनाने के लिए जागरूक किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जल जीव मिशन के तहत गांवों में अन्य योजनाओं के संसाधनों को उपलब्ध कराकर सार्वजनिक व्यय प्रभावी समाविष्टिकरण के साथ विवेकपूर्ण तरीके से न्यायसंगत रूप से प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। वेबिनार के अन्य प्रमुख वक्ताओं में श्री मुरलीधरन, उप सलाहकार, एनजेजेएम, श्री एच. हिंगोरानी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (पीएचई), श्री राणा आर. सिंह, पीएचई विशेषज्ञ, एनजेजेएम प्रमुख थे। जेजेएम के तहत बेहतर निष्कर्षों के लिए एक पैन इंडिया ज्ञान-नेटवर्क के निर्माण के अनुसरण में, सूचना और अच्छी प्रथाओं के फलदायी आदान-प्रदान में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है । एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाने के लिए, मासिक समाचार पत्रों के साथ-साथ वेबिनार के रूप में **'जल जीवन संवाद'** की शुरुआत की गई है।

हर घर जल
जल जीवन मिशन

हर घर जल संवाद

"**कैच द रेन**" वर्षाजल संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता पैदा करने हेतु संरचित एक कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जाएगा और जनता को वर्षाजल बचाने की तकनीकों से अवगत कराया जाएगा।

माननीय मंत्री, जल शक्ति, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत

लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें

Jal Jeevan Mission, India | @jaljeevan_ | Jal Jeevan Mission

@jaljeevanmission | jjm.gov.in

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल और स्वच्छता विभाग
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन
नई दिल्ली - 110 003
ई-मेल: njjm-ddws@gov.in